वर्ष-11, अंक-1, अक्टूबर-2025

मूल्य: ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

YASHODA MEDICITY

उत्तम स्वास्थ्य के लिए अब

गाजियाबाद ही सर्वोत्तम

शिक्षा में नवाचार
प्रगति का आधार

बेसिक शिक्षा : विजन@2047

अवस्थापना कार्य

- प्रत्येक न्याय पंचायत में मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय की स्थापना (सर्वोत्तम श्रेणी की सुविधाएं, अत्याधुनिक कक्षाएं, डिजिटल उपकरण)
- 'करो और सीखो' सिद्धांत के आधार पर कौशल केंद्रों की स्थापना (नवाचार, समस्या समाधान, रचनात्मकता, सहयोग एवं डिजिटल साक्षरता)

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

मजबूत नींव एवं अंतर्राष्ट्रीय लर्निंग आउटकम

कक्षा-3 तक 100% आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता, कक्षा-8 तक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रेड-स्तरीय अधिगम

शिक्षक गुणवत्ता एवं नवाचार

सतत प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं नवाचार के लिए सक्षम बनाना, संकुल स्तर पर 100 शिक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यशाला हेतु बहुउद्देश्यीय हॉल

प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्तर पर काउंसलर की नियुक्ति

लर्निंग बाय डूइंग

उच्च प्राथमिक शिक्षा में 'करो और सीखो' पद्धति को पूरी तरह से लागू करना

छात्रों में व्यावहारिक कौशल के साथ ही रचनात्मक सोच का विकास करना

उत्तर प्रदेश को देश की शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी राज्य के रूप में मॉडल बनाना

प्रबंधन सूचना प्रणाली

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% एवं ट्रांजिशन रेट 100% प्राप्त करना

छात्र-छात्राओं का ड्रॉप आउट पूरी तरह समाप्त करना

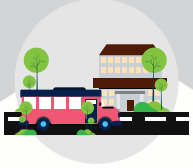

कस्तूरबा बालिका विद्यालय

- सभी छात्राओं को प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, नवाचार, खेलकूद, स्टार्टअप एवं अन्य क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाने हेतु दक्ष/निपुण बनाना
- सभी छात्राओं को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाना, ज्ञान, कौशल, मूल्यों एवं आत्मविश्वास के साथ सशक्तीकरण करना
- कम से कम 200 बालिकाओं को राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं एवं 25 छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना
- कस्तूरबा बालिका विद्यालयों को स्किल हब के रूप में विकसित किया जाना, जिससे छात्राओं को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

बुनियादी ढांचा एवं शिक्षण प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता एवं निगरानी, व्यक्तिगत शिक्षा एवं नवाचार हेतु प्रमुख गतिविधियां बाल वाटिका की स्थापना, शिक्षक भर्ती एवं प्रशिक्षण, गुणवत्ता सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण सुदृढ़ीकरण, निगरानी प्रणाली की स्थापना, व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, नवाचार एवं तकनीकी निगरानी आदि

माध्यमिक शिक्षा : विजन @2047

- व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा
- SDG-4 के अनुरूप समता आधारित शिक्षा
- असेवित बस्तियों का शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुरूप अवस्थापना सुविधाएं
- रोबोटिक्स, एआई एवं वीआर की प्रयोगशालाएं
- प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल पुस्तकालय नेटवर्क
- स्कूली खेलों हेतु अंतरराष्ट्रीय सुविधा का विकास

काम दमदार-डबल इंजन सरकार

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश | माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

वर्ष- 11 अंक- 1

अक्टूबर-2025

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

अन्दर के पेजों में...

सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देते हैं मोदी, ट्रंप को भी कूटनीतिक चाल से दी मात — पेज 03

आसमान में नई ऊंचाइयां छू रहा उत्तर प्रदेश हवाई यात्री और कार्गो ट्रैफिक में रिकॉर्ड वृद्धि — पेज 07

संघ के 100 साल: पंच परिवर्तन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ — पेज 10

बसपा ने फिर दिखाई ताकत, मायावती के सियासी दांव से सपा को 'तनाव' — पेज 12

गाजियाबाद को हरित, स्मार्ट और नागरिक अनुकूल शहर बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं डीएम रविंद्र कुमार मंदार — पेज 24

अलविदा 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' — पेज 55

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों और से हो रही चुनावी सौदेबाजी

ललित कुमार
सम्पादक

बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी और विपक्षी दलों की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए घोषणाओं और वादों का सिलसिला जारी है। जनता अपना समर्थन किस राजनीतिक दल या पक्ष को दे, यह इस पर निर्भर करता है कि वह किसे अपने या व्यापक हितों के अनुकूल समझती है। यह लोकतंत्र का एक जीवन-तत्त्व है कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए जनता के हितों को केंद्र में रखें। मगर इस क्रम में पिछले कुछ वर्षों में हुआ यह है कि लगभग सभी राजनीतिक दल ऐन चुनावों के वक्त आम लोगों के सामने उनके हित के नाम पर ऐसे वादे करती हैं कि साधारण मतदाता कई बार सभी पक्षों की ईमानदारी का समग्र मूल्यांकन करने के बजाय तात्कालिक घोषणाओं से प्रभावित हो जाते हैं। इसका स्वाभाविक असर मतदान पर पड़ता है, लेकिन यह समझने की कोशिश नहीं की जाती कि चुनावी सौदेबाजी से देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक शुचिता किस तरह प्रभावित होती है। बिहार में वोट जुटाने के मकसद से सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन की ओर से मतदाताओं को रिझाने के लिए कई तरह की सौगात देने की घोषणाएं की गई हैं। अगर वे सचमुच पूरी होती हैं, तो इसके लिए संसाधन कहां से आएंगे, इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर किसी में चिंता नहीं दिखाई देती है। मसलन, चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब सवा करोड़ महिलाओं को दस-दस हजार रुपए की राशि दी गई, जिससे राज्य के खजाने से बारह हजार करोड़ रुपए से ज्यादा व्यय हुए। इसी तरह, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली, जीविका, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई। दूसरी ओर, विपक्षी महागठबंधन की ओर से सबसे बड़ी घोषणा हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने की हुई। इसके अलावा, हर जीविका दीदी को तीस हजार रुपए वेतन और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया। जो घोषणाएं सत्ता और विपक्षी दलों ने बिहार के लोगों के लिए की हैं, उनकी जरूरत दरअसल इसलिए पड़ी कि राज्य में अब तक जरूरत के मुताबिक सरकारी कल्याण कार्यक्रम पूरे नहीं किए गए, व्यापक बेरोजगारी गंभीर समस्या बनी हुई है और एक बड़ी आबादी के लिए अभाव का सामना करना एक रोजमर्रा की मुश्किल है। सवाल है कि सभी दलों को आखिर इस तरह के वादे या घोषणाएं करने की जरूरत तभी क्यों पड़ती है, जब चुनाव सिर पर होते हैं। सत्ता में रहते हुए उनकी प्राथमिकताएं आम जनता के बजाय कुछ और क्यों हो जाती हैं? यह एक आम हकीकत है कि अगर सरकार के सामने बेरोजगारी या अन्य समस्याओं का जिक्र किया जाता है, तो वह धन की कमी का रोना रोने लगती है। फिर चुनावी सौदेबाजी के तहत परोसी जाने वाली मुफ्त की सुविधाओं के लिए धन और संसाधन कहां से आ जाते हैं? हालांकि एक पक्ष यह भी है कि अगर कोई भी सरकार ईमानदार इच्छाशक्ति के साथ काम करे, तो वह नागरिकों को आर्थिक-सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए सब कुछ कर सकती है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि कल्याण कार्यक्रमों का स्वरूप क्या है। अगर कोई सुविधा आम जनता को मुफ्त मुहैया कराई जाती है तो किसी न किसी रूप में उसकी कीमत लोगों को ही चुकानी पड़ती है।

सवाल है कि सभी दलों को आखिर इस तरह के वादे या घोषणाएं करने की जरूरत तभी क्यों पड़ती है, जब चुनाव सिर पर होते हैं। सत्ता में रहते हुए उनकी प्राथमिकताएं आम जनता के बजाय कुछ और क्यों हो जाती हैं? यह एक आम हकीकत है कि अगर सरकार के सामने बेरोजगारी या अन्य समस्याओं का जिक्र किया जाता है, तो वह धन की कमी का रोना रोने लगती है। फिर चुनावी सौदेबाजी के तहत परोसी जाने वाली मुफ्त की सुविधाओं के लिए धन और संसाधन कहां से आ जाते हैं?

सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देते हैं मोदी, ट्रंप को भी कूटनीतिक चाल से दी मात

उल्लेखनीय है कि हाल के महीनों में ट्रंप ने कई बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए 'राजी' किया है, या कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' को रोक दिया था। यह ऐसे बयान हैं जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।

संजीव कुमार

आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल रूप से शामिल होने के निर्णय ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार असत्य और विवादास्पद बयानों के बीच मोदी का यह कदम केवल एक राजनैतिक निर्णय नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीतिक चाल भी है। जहाँ एक ओर विपक्ष विशेषकर कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि मोदी ट्रंप से मिलने से 'डर' रहे हैं, वहीं वस्तुतः यह निर्णय भारतीय विदेश नीति की परिपक्वता और आत्मविश्वास का परिचायक है।

उल्लेखनीय है कि हाल के महीनों में ट्रंप ने कई बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए 'राजी' किया है, या कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' को रुकवा दिया था। यह ऐसे बयान हैं जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। यह स्पष्ट है कि ट्रंप घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रचार का औजार बना रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का उनसे औपचारिक मुलाकात से बचना भारत की कूटनीति की गंभीरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। सीधे आमने-सामने मिलना ट्रंप को अपने राजनीतिक प्रचार में भारत के नाम का उपयोग करने का अवसर देता– जो न केवल भारत की तटस्थता बल्कि उसकी वैश्विक छवि को भी प्रभावित कर सकता था। साथ ही मोदी का

वर्चुअल रूप से आसियान सम्मलेन में शामिल होना इस 'राजनीतिक जाल' से बचने का संतुलित मार्ग भी है। दूसरी ओर, कांग्रेस का आरोप कि प्रधानमंत्री 'ट्रंप से डर रहे हैं', वस्तुतः सतही और अव्यावहारिक है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने भारत-अमेरिका संबंधों को समान साझेदारी के आधार पर विकसित किया है न कि किसी भय या दबाव के अधीन। वर्तमान निर्णय भी उसी आत्मनिर्भर विदेश नीति का हिस्सा है जहाँ भारत अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है। मोदी का आसियान सम्मेलन में वर्चुअल भागीदारी का फैसला न तो अमेरिका से दूरी बनाना है, न ही ट्रंप के प्रति विरोध। यह निर्णय उस संतुलनकारी कूटनीति का हिस्सा है जिसने भारत को रूस और अमेरिका दोनों से समान दूरी बनाए रखते हुए अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाया है।

भारत आज न तो किसी धुरी का हिस्सा है और न ही किसी के दबाव में झुकता है। जब ट्रंप भारत पर ऊँचे शुल्क लगाते हैं या रूस से तेल खरीदने पर दबाव डालते हैं, तब भी भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए संयम बनाए रखता है। यही रणनीति मोदी ने इस मुलाकात से बचकर अपनाई है– यानी 'ट्रंप को उनकी ही भाषा में जवाब देना', लेकिन बिना टकराव के। मोदी का आसियान में वर्चुअल उपस्थिति का निर्णय किसी निष्क्रियता का संकेत नहीं है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने आसियान के मंच पर भारत की Act East Policy को निरंतर गति दी है। यह वही नीति है जिसने दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत किया है। साथ ही वर्चुअल भागीदारी का अर्थ यह नहीं कि भारत पीछे हट रहा है– बल्कि यह निर्णय दशार्ता है कि भारत तकनीक और संवाद दोनों के माध्यम से वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय बना हुआ है। डिजिटल उपस्थिति ने अब कूटनीति की सीमाएँ बदल दी हैं और मोदी का यह निर्णय उस आधुनिक यथार्थ को स्वीकार करने का संकेत है।

साथ ही मोदी के इस निर्णय का सबसे बड़ा प्रभाव भारत की स्वतंत्र वैश्विक छवि के रूप में सामने आएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति से न मिलना यह दिखाता है कि भारत किसी भी देश के राजनीतिक समीकरणों के आगे नहीं झुकता। जहाँ एक ओर ट्रंप एशिया यात्रा में तीन देशों के साथ दिखावटी संपर्क बनाना चाहते हैं, वहीं भारत ने नीतिगत गरिमा को प्राथमिकता दी है। यह संदेश स्पष्ट है– भारत संवाद तो करेगा, लेकिन अपने समय, अपने शर्तों और अपने हितों के आधार पर।

प्रधानमंत्री मोदी का आसियान सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने का निर्णय न तो किसी भय का प्रतीक है और न ही अवसर खोने का। यह भारत की परिपक्व, आत्मविश्वासी और बहुपक्षीय विदेश नीति का प्रमाण है जहाँ कूटनीति का लक्ष्य केवल मित्रता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गरिमा और संतुलन की रक्षा भी है। दूसरी ओर, ट्रंप की राजनीति आज अनिश्चितता, बयानबाजी और घरेलू नाटकीयता से घिरी हुई है। ऐसे में भारत का संयमित रुख ही वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन है।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं– परंतु शांत और रणनीतिक ढंग से। ट्रंप जैसे नेताओं के साथ जो सार्वजनिक बयानबाजी और दबाव की राजनीति करते हैं, उनके सामने मोदी ने उसी शैली को उलटकर अपनी शांति, संयम और सधी हुई दूरी के माध्यम से जवाब दिया है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जवाब हमेशा शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से भी दिया जा सकता है।

इस बार भी ट्रंप की बयानबाजी के जवाब में मोदी ने अपनी उपस्थिति को प्रतीकात्मक बना कर यह दिखा दिया कि भारत किसी भी शक्ति से कम नहीं। दरअसल, यह मोदी का 'डिप्लोमैटिक मास्टरस्ट्रोक' है जिसने ट्रंप को उनके ही खेल में मात दे दी और दुनिया को दिखा दिया कि भारत के प्रधानमंत्री आज वैश्विक राजनीति के सबसे सधे हुए खिलाड़ी हैं। बहरहाल, कांग्रेस के आरोपों से परे, सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल भारत की वैश्विक साख की रक्षा की है, बल्कि यह भी दिखाया है कि 21वीं सदी का भारत किसी के 'political optics' का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि वह स्वयं अंतरराष्ट्रीय मंचों की दिशा तय करेगा।

कुल मिलाकर देखें तो मोदी का यह निर्णय किसी 'डर' का नहीं, बल्कि दूरदर्शिता का परिणाम है– और यही वह बिंदु है जहाँ भारत की कूटनीति अपनी परिपक्वता के चरम पर खड़ी दिखाई देती है।

संबंधों को पटरी पर लाने की चुनौती

गोर का भारत में राजदूत के साथ-साथ दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों का विशेष दूत भी होना एक राजनीतिक संकेत है कि अमेरिका भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्र को अब सीधे राष्ट्रपति की प्राथमिकता के रूप में देख रहा है, परंतु यह दोहरी भूमिका भारत के लिए दुविधा का विषय भी है। नई दिल्ली लंबे समय से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे दक्षिण एशिया के पारंपरिक 'भारत-पाकिस्तान ढांचे में न बांधा जाए।

अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर ने पहले ही दिन भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से उनकी बैठकें संकेत हैं कि वाशिंगटन भारत के साथ अपने रिश्ते को नई गति देने के मूड में है। इस सौहार्दपूर्ण शुरूआत के पीछे गोर के लिए चुनौतियों का एक जटिल जाल बिछा हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता ने जहां संबंधों में नई ऊर्जा डाली है, वहीं दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद,

उज्जवल रस्तौगी

तकनीकी साझेदारी की जटिलताएं और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। गोर के लिए सबसे बड़ी कसौटी यह होगी कि वे व्यक्तिगत निकटता को नीति में बदलें और इन विरोधाभासों को समेटते हुए संबंधों को नई दिशा दें।

गोर का भारत में राजदूत के साथ-साथ दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों का विशेष दूत भी होना एक राजनीतिक संकेत है कि अमेरिका भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्र को अब सीधे राष्ट्रपति की प्राथमिकता के रूप में देख रहा है, परंतु यह दोहरी भूमिका भारत के लिए दुविधा का विषय भी है। नई दिल्ली लंबे समय से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे दक्षिण एशिया के पारंपरिक 'भारत-पाकिस्तान ढांचे में न बांधा जाए। गोर के लिए यह चुनौती होगी कि वे भारत की वैश्विक भूमिका को बनाए रखते हुए अपने क्षेत्रीय दायित्वों का निर्वाह करें। उनकी सबसे कठिन परीक्षा आर्थिक मोर्चे पर होगी।

ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा दिया है।

अमेरिका का दावा है कि भारत के ऊंचे आयात शुल्क और रूस से तेल खरीद जैसी नीतियां असंतुलित हैं।

इसके जवाब में भारत ने अपने हितों की रक्षा पर जोर दिया है। संभावित व्यापार समझौता महीनों से ठप पड़ा है। ऐसे में गोर को इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना होगा, वह भी बिना किसी घरेलू राजनीतिक विवाद के। प्रौद्योगिकी साझेदारी भी उनके एजेंडे का एक संवेदनशील बिंदु है। भारत रक्षा और नवाचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहता है, जबकि अमेरिका अपनी बौद्धिक संपदा और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सतर्क है। सेमीकंडक्टर, एआइ और डाटा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तो हैं, पर नीतिगत स्पष्टता की कमी दोनों पक्षों को सतर्क रखती है। गोर का कार्य यह साबित करना होगा कि वाशिंगटन की तकनीकी नीति चीन को लेकर है, भारत को लेकर नहीं।

रक्षा सहयोग के क्षेत्र में गोर को एक सकारात्मक आधार मिला है। दोनों देशों के बीच हुए कोमकासा और बीईसीए जैसे समझौते सामरिक साझेदारी के नए युग की नींव बन चुके हैं। फिर भी भारत अमेरिका से अधिक तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन चाहता है, जबकि वाशिंगटन रूस से भारत के सैन्य संबंधों पर दबाव डालता है।

गोर को इस संतुलन को साधना होगा, ताकि भारत की रक्षा स्वायत्तता प्रभावित न हो और अमेरिका की रणनीतिक अपेक्षाएं भी पूरी हों। दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में चुनौती और गहरी है। ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति हालिया रुझान- इस्लामाबाद के नेतृत्व से मुलाकात और उसके ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी निवेश के संकेत दिल्ली के लिए असहज हैं। भारत को यह आशंका है कि कहीं वाशिंगटन पुनः री-हाइफनेशन यानी भारत-पाकिस्तान समानांतर नीति की ओर न लौट जाए।

गोर की दोहरी जिम्मेदारी-दिल्ली और इस्लामाबाद, दोनों से संपर्क इस चिंता को और गहरा करती है। उन्हें भारत को यह विश्वास दिलाना होगा कि ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम रणनीतिक गणित का हिस्सा है, न कि नीति परिवर्तन का। महत्वपूर्ण खनिजों पर गोर और मोदी के बीच चर्चा यह दिखाती है कि अमेरिका इस क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। दोनों देश चीन पर निर्भरता कम करने और फ्रेंड-शोरिंग के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के पक्षधर हैं, पर भारत की खनन नीतियां अभी भी जटिल हैं।

यदि गोर यहां ठोस निवेश या संयुक्त परियोजनाएं आगे बढ़ा पाते हैं तो यह उनके कार्यकाल की एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। आव्रजन नीति और एच-1बी वीजा व्यवस्था पर भी उन्हें सावधानी से चलना होगा। भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका की कड़ी वीजा नीति चिंता का विषय रही है।

गोर को इन घरेलू राजनीतिक बाधाओं को समझाते हुए भी भरोसे का माहौल बनाना होगा। गोर के पास एक बड़ा लाभ यह है कि वे सीधे राष्ट्रपति तक पहुंच रखते हैं, पर यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। यदि वे ट्रंप की व्यक्तिगत सद्भावना को ठोस नीतिगत परिणामों में बदलने में सफल रहते हैं तो न केवल संबंधों को पुनर्जीवित करेंगे, बल्कि उन्हें नई ऊंचाई भी देंगे। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका का सहयोग अनिवार्य है। चीन की आक्रामकता, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला के पुनसंर्तुलन के युग में दोनों देशों की साझेदारी ही स्थिरता की गारंटी है। गोर के आगमन से यह उम्मीद बंधती है कि संवाद की रफ्तार फिर से बढ़ेगी, रक्षा-प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्रों में प्रगति होगी और असहमतियों के बावजूद सहयोग का दायरा विस्तृत होगा।

आसमान में नई ऊंचाइयां छू रहा उत्तर प्रदेश हवाई यात्री और कार्गो ट्रैफिक में रिकॉर्ड वृद्धि

घरेलू यात्रियों में 15.7% और एयर कार्गो में 19.1% का आया उछाल

- वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे शहर बने उत्तर प्रदेश की हवाई ग्रोथ के इंजन
- अप्रैल से अगस्त 2025 की अवधि में उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों से 60 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर
- इन तीन महीनों में भारत के कुल हवाई यातायात में राज्य की हिस्सेदारी 3.52% तक पहुंची

इंद्रेश शर्मा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब न केवल सड़क पर, बल्कि आसमान में भी विकास की उड़ान भर रहा है। राज्य की हवाई कनेक्टिविटी और यात्री संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे प्रदेश अब भारत की हवाई ग्रोथ स्टोरी में एक अहम किरदार बन गया है। अप्रैल से अगस्त 2025 की अवधि में उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 14.6% बढ़कर 60.02 लाख हो गई है। वहीं इस अवधि में भारत के कुल हवाई यातायात में राज्य की हिस्सेदारी 3.52% तक पहुंच गई, जो 2024 की तुलना में 34 बेसिस पॉइंट्स अधिक है। इससे साफ है कि अब देश के हर 30 में से एक हवाई यात्री उत्तर प्रदेश से यात्रा कर रहा है। राज्य में हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 'कनेक्टेड यूपी, समृद्ध यूपी' विजन के तहत पेश की थी। उनका लक्ष्य रहा है कि हर क्षेत्र, हर जिला आधुनिक परिवहन से जुड़े ताकि पर्यटन, व्यापार और रोजगार में नई गति आए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ इस रफ्तार में और भी वृद्धि होगी और सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी कनेक्टिविटी के नए अवसर प्राप्त होंगे।

2017 से 2025 तक यूपी की हवाई यात्रा का सफर

साल 2016-17 में जहां उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों से 59.97 लाख यात्री यात्रा करते थे, वहीं FY2024-25 में यह संख्या बढ़कर 142.28 लाख तक पहुंच गई। इनमें 129.29 लाख घरेलू और 12.99 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री शामिल रहे। इस दौरान राज्य का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) 10.1% रहा, जो एविएशन सेक्टर में तेजी से बढ़ती मांग को दशार्ता है। कोविड-19 महामारी के दौरान F 2020-21 में यात्री संख्या 48.35 लाख तक गिर गई थी, लेकिन यूपी ने सबसे तेज रिकवरी दिखाई। महज दो वर्षों में यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई, जो राज्य की मजबूत हवाई नीति और बेहतर प्रबंधन का प्रमाण है। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में हवाई यात्रियों की संख्या में 25.9 प्रतिशत का ग्रोथ दर्ज किया गया है, जबकि 2023-24 और 2024-25 में अप्रैल-अगस्त माह के बीच कंपैरिजन करें तो यह ग्रोथ 14.6% रही। इस दौरान डॉमेस्टिक एयर पैसेंजर्स में 15.7% और इंटरनेशनल पैसेंजर्स की संख्या में 4.3% ग्रोथ दर्ज की गई।

कार्गो ट्रैफिक में भी जबरदस्त वृद्धि

उत्तर प्रदेश अब व्यापार और निर्यात के लिए भी एयर कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र बन रहा है। FY2016-17 से FY2024-25 तक राज्य के एयर कार्गो में 19.1% का CAGR दर्ज किया गया है। यह 5.89 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 28.36 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। FY2024-25 में लखनऊ एयरपोर्ट ने 22,099 मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया, जबकि वाराणसी में 27.7% और प्रयागराज में 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2023-24 से 2024-25 के बीच टोटल ग्रोथ 9.4% रही और इस दौरान एयर कॉर्गो 25,915 मीट्रिक टन से 28,356 मीट्रिक टन पहुंच गया। अप्रैल-अगस्त 2025 में कानपुर (165%) और आगरा (247%) में रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज हुई जो बताता है कि राज्य के इंडस्ट्रियल क्लस्टर अब अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जुड़ रहे हैं। अप्रैल-अगस्त 2025 में राज्य का भारत के कुल एयर कार्गो में हिस्सा 0.79% हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 बेसिस पॉइंट अधिक है।

साकार हो रहा योगी सरकार का विजन

उत्तर प्रदेश सिविल एविएशन के डायरेक्टर ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि हवाई कनेक्टिविटी सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार, पर्यटन और निवेश की नई शक्ति है। जब हर जिले से उड़ान संभव होगी, तो हर नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा होगा। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अयोध्या, कुशीनगर और जेवर (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट) जैसे नए हवाई अड्डों का तेजी से विकास किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की ओर अग्रसर होगा। इसी क्रम में प्रदेश सरकार कई नए एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है।

अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी बने स्टार परफॉर्मर

राज्य के कई शहरों ने इस ग्रोथ में अहम योगदान दिया है। 2023-24 से 2024-25 के बीच वाराणसी में 34.4%, प्रयागराज में 76.4%, गोरखपुर में 27.6% और कानपुर में 13.3% की वृद्धि दर्ज की गई। यह दशार्ता है कि धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी ने यात्री संख्या को तेजी से बढ़ाया है। खासतौर पर अयोध्या एयरपोर्ट, जिसे मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर समर्पित किया था, अब उत्तर भारत के सबसे तेजी से बढ़ते टर्मिनल्स में शामिल है। 2023-24 में जहां 2 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ने यहां से हवाई उड़ान भरी थी तो वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 11 लाख से अधिक पहुंच गया। वहीं प्रयागराज और वाराणसी से भी धार्मिक और व्यावसायिक उड़ानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रयागराज में 2023-24 में 6 लाख से अधिक एयर पैसेंजर्स ने यात्रा की तो वहीं 2024-25 में यह संख्या 10.77 लाख से अधिक पहुंच गई। इसी तरह वाराणसी में 2023-24 में करीब 30 लाख एयर पैसेंजर्स यात्रा कर रहे थे तो वहीं 2024-25 यह संख्या 40 लाख का आंकड़ा पार कर गई। गोरखपुर में 2023-24 में 6.8 लाख की तुलना में 2024-25 में 8.67 लाख से अधिक हवाई यात्रियों ने सफर किया। लखनऊ ने भी अपनी रफ्तार में इजाफा किया है, जहां 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 4.1% की वृद्धि हुई है।

नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तर प्रदेश ने लिख रहा नया अध्याय

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1.86 करोड़ पात्र महिलाओं के खाते में 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने के अलावा योगी सरकार आधी आबादी के सशक्तिकरण को मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में नारी सम्मान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बीते वर्षों में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। लगातार चल रहे इन प्रयासों ने न केवल महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा किया है, बल्कि समाज में सम्मान, आत्मविश्वास और समानता की भावना को भी मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश आज नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश कर रहा है।

- कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक 26 लाख 34 हजार बेटियों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, पोषण और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार साबित हुई है।
- महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व दिलाने के लिए घरौनी योजना चलाई गई है, जिसके तहत 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को गृहस्वामित्व प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को अधिकार और आत्मसम्मान दोनों प्रदान किए हैं।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए प्रदेश में 10 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए हैं, जिनसे 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों को समय-समय पर रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिससे महिलाएं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर रही हैं।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 4 लाख 67 हजार से अधिक महिलाओं का विवाह संपन्न कराया गया है। प्रत्येक विवाह पर ₹1 लाख की आर्थिक सहायता ने गरीब परिवारों के आर्थिक बोझ को कम किया है।
- महिलाओं की दैनिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 2 करोड़ 41 लाख घरों में नल से जल उपलब्ध कराया गया है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को राहत मिली है, जिन्हें पहले पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।
- महिला स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिए ₹1 करोड़ तक की संपत्ति खरीद पर महिलाओं को 1% स्टाम्प शुल्क की छूट दी गई है।
- सरकारी सेवाओं में 20% आरक्षण के प्रावधान से अब तक 1 लाख 75 हजार महिलाओं को रोजगार मिला है, जिनमें से 44,177 महिलाओं की भर्ती पुलिस विभाग में हुई है।
- नारी सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अपराधियों को सजा दिलाने में प्रदेश देश में अग्रणी है। कई मामलों में रिपोर्ट दर्ज होने से लेकर सजा तक का समय सिर्फ 40 दिन रहा है।
- निराश्रित महिलाओं को ₹1,000 मासिक भत्ता देने की व्यवस्था से 36 लाख 75 हजार महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 2 लाख महिलाएं और बीसी सखी योजना के तहत 39 हजार महिलाएं ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनी हैं।

लाभार्थी महिलाओं ने सीएम योगी का जताया आभार

निशुल्क सिलेंडर प्राप्त करने वाली लाभार्थी महिलाओं ने लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दीपावली के इस उपहार के लिए धन्यवाद दिया और महिलाओं की समृद्धि और उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने को लेकर आभार जताया।

लाभार्थी लीलावती ने कहा कि इस निशुल्क सिलेंडर के लिए मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यह दीपावली के पावन अवसर पर हमारे लिए अमूल्य उपहार है। वहीं, लखनऊ की निशा चौहान ने कहा कि इस सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। पहले हम चूल्हे में खाना बनाते थे, जिसके चलते हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए इस उपहार से हमें बहुत लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस उपहार के लिए धन्यवाद करते हैं।

पंच परिवर्तन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

समरसता भारतीय समाज की आत्मा है। यह केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहार है। संघ का मानना है कि जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव न रहे, तभी भारत अपने सांस्कृतिक स्वरूप को साकार कर सकेगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में केवल अपनी यात्रा का उत्सव नहीं मना रहा, बल्कि भारत के पुनर्निर्माण की दिशा में एक विचार-यात्रा प्रारंभ कर रहा है। इस यात्रा का केंद्र है 'पंच परिवर्तन', एक ऐसी रूपरेखा जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों स्तरों पर सकारात्मक परिवर्तन की मांग करती है। संघ का यह प्रयास केवल संगठनात्मक ऊर्जा का विस्तार नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना को नई दिशा देने वाला सामाजिक संकल्प है। भारत आज सामाजिक विषमताओं, पारिवारिक विघटन, पर्यावरणीय असंतुलन, आर्थिक परनिर्भरता और नागरिक दायित्वों की शिथिलता जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों में 'पंच परिवर्तन' केवल विचार नहीं, बल्कि इन समस्याओं के समाधान का समग्र मार्गदर्शन बनकर सामने आता है। यह पांच परिवर्तन—सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, 'स्व' आधारित जीवनशैली और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक निर्माण—भारतीय समाज के नवजागरण की आधारशिला के रूप में उभरते हैं।

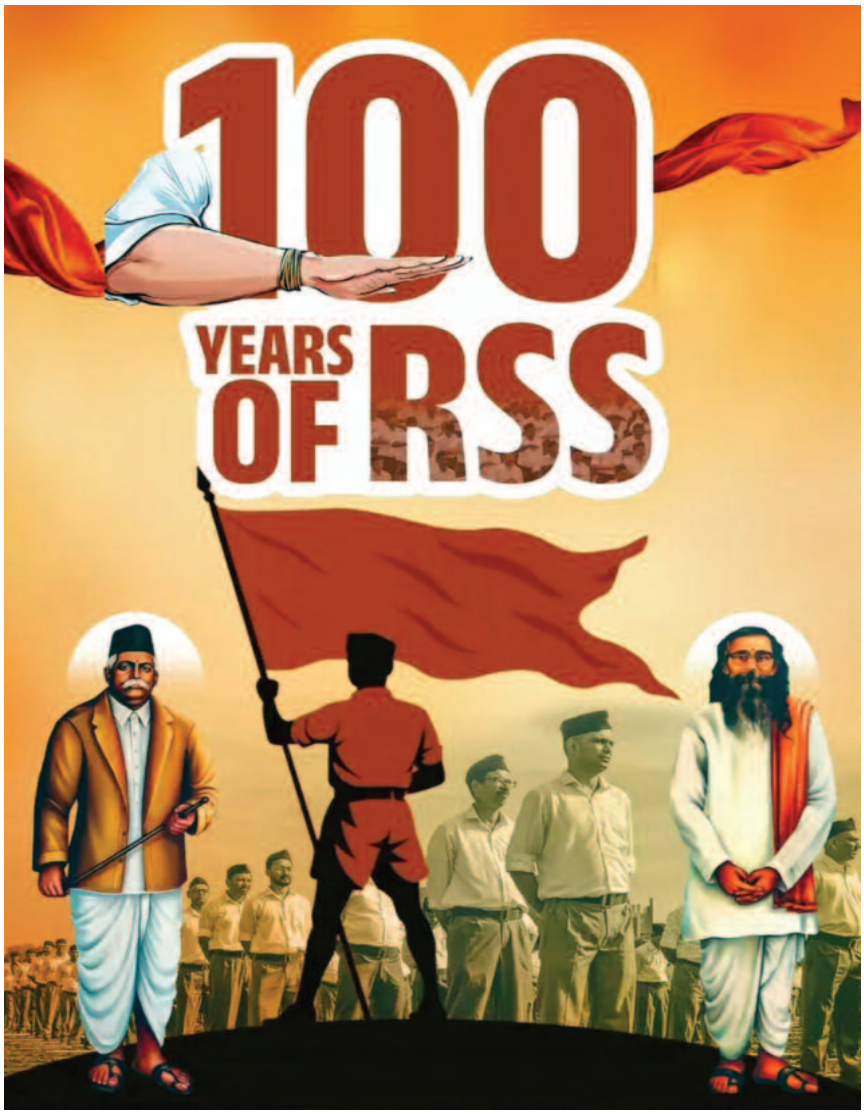

सामाजिक समरसता— विविधता में एकता का सजीव दर्शन

समरसता भारतीय समाज की आत्मा है। यह केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहार है। संघ का मानना है कि जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव न रहे, तभी भारत अपने सांस्कृतिक स्वरूप को साकार कर सकेगा। समानता और आत्मीयता – यही समाज को जोड़ने की वास्तविक शक्ति है। इसी भावना को साकार करने के लिए संघ के स्वयंसेवक गाँव-गाँव में सहभोजन, समरस उत्सव और संयुक्त सेवा परियोजनाएँ आयोजित कर रहे हैं। 'एक मंदिर झ एक जलस्रोत - एक श्मशान' जैसे अभियानों ने ग्रामीण समाज में बंधुता का वातावरण बनाया है। श्रीराम और केवट का प्रसंग आज भी इस समरसता का प्रतीक है, जहाँ सम्मान और आत्मीयता जाति या वर्ग से ऊपर उठ

जाती है।

कुटुंब प्रबोधन–परिवार ही राष्ट्र की प्रथम इकाई

भारतीय संस्कृति में परिवार केवल सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि संस्कार की प्रयोगशाला है। आज के यांत्रिक जीवन में जब संवाद घट रहा है और उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, तब कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस होती है। संघ के 'परिवार प्रबोधन अभियान' के अंतर्गत देशभर में संयुक्त भोजन, साप्ताहिक पारिवारिक संवाद, सांस्कृतिक आयोजन और संस्कार वर्ग जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। इनसे पीढ़ियों के बीच संवाद पुनः स्थापित हो रहा है और परिवारों में भारतीय जीवन-मूल्य पुनर्जीवित हो रहे हैं। सशक्त परिवार ही सशक्त राष्ट्र की नींव रखता है। बालगोकुलम् और संस्कार भारती जैसी पहलें इस कुटुंब संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान कर रही हैं।

पर्यावरण संरक्षण–प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव

भारत का दृष्टिकोण सदैव 'प्रकृति मातरं वंदे' का रहा है। संघ इस परंपरा को आधुनिक संदर्भ में पुनः स्थापित कर रहा है। वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, प्लास्टिक-त्याग, जैविक खेती और नदी-सफाई जैसे अभियानों के माध्यम से संघ के स्वयंसेवक समाज में पर्यावरणीय संतुलन की चेतना फैला रहे हैं। प्रकृति केवल संसाधन नहीं, बल्कि सृजन की सहयात्री है। संघ का अभियान 'एक वृक्ष – मातृभूमि के नाम' इस कृतज्ञता का प्रतीक है। यह केवल पर्यावरणीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-दर्शन की पुनर्स्थापना है।

'स्व' आधारित जीवनशैली–आत्मनिर्भरता का सांस्कृतिक स्वरूप

'स्व' आधारित जीवनशैली, पंच परिवर्तन का चौथा आयाम है। यह आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ-साथ सांस्कृतिक आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। संघ का 'स्वावलंबन अभियान' ग्रामीण और शहरी स्तर पर स्थानीय उत्पादन, हस्तशिल्प, खादी, चरखा, गौ-आधारित उद्योग और स्वदेशी उपक्रमों को प्रोत्साहन दे रहा है। यह केवल आर्थिक नीति

नहीं, बल्कि आत्मगौरव का आंदोलन है। स्वदेशी केवल व्यापार की नीति नहीं, आत्मा की पुकार है। विदर्भ, केरल और पूर्वोत्तर भारत में ऐसे कई संघ-प्रेरित लघु उद्योग आत्मनिर्भरता के सशक्त उदाहरण बने हैं। 'स्व' का यह भाव भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सांस्कृतिक रूप से स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर है।

राष्ट्रीय चेतना और कर्तव्यपरायण नागरिक निर्माण

संघ के विचार में, राष्ट्र निर्माण का मूल कर्तव्यनिष्ठ नागरिक है। शाखाओं और प्रशिक्षण शिविरों में स्वयंसेवकों को सिखाया जाता है कि अधिकारों से पहले कर्तव्य का बोध आवश्यक है। जब हर व्यक्ति राष्ट्र को परिवार मानेगा, तब भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। संघ के आपदा राहत, ग्राम स्वच्छता, शिक्षा सेवा केंद्र और स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से लाखों स्वयंसेवक सेवा और अनुशासन की भावना से समाज में सक्रिय हैं। यह परिवर्तन नागरिकता की एक नयी परिभाषा प्रस्तुत करता है, जहाँ 'राष्ट्र प्रथम' सर्वोच्च मूल्य बन जाता है।

पंच परिवर्तन का यह सूत्र वास्तव में भारत के नवजागरण की दिशा में अग्रसर एक जीवंत अवधारणा है। यह भारत को सामाजिक रूप से समरस, पारिवारिक रूप से सुदृढ़, पर्यावरणीय रूप से संतुलित, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और नागरिक रूप से कर्तव्यनिष्ठ बनाना चाहता है। संघ की शाखाएँ, सेवा योजनाएँ, शिक्षा संस्थान और ग्राम विकास कार्य झ सभी इस पंच परिवर्तन के सूत्र से जुड़े हुए हैं। यह केवल विचारधारा नहीं, बल्कि राष्ट्र पुनर्निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। यह विचार संघ की उस गहराई को प्रकट करता है जो भारत को आत्मा से जोड़ती है, कर्म से सशक्त करती है और विचार से प्रबुद्ध बनाती है। जब समाज का हर घटक अपने स्व की पहचान कर कर्तव्य के मार्ग पर चलता है, तब राष्ट्र केवल भौगोलिक इकाई नहीं रह जाता, वह जीवंत चेतना बन उठता है। यही पंच परिवर्तन की आत्मा है – जो भारत को एक बार फिर विश्व में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के मंत्र का ध्वजवाहक बना सकती है।

बसपा ने फिर दिखाई ताकत, मायावती के सियासी दांव से सपा को 'तनाव'

बसपा रैली में बहिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद की लॉन्चिंग के साथ-साथ मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता सतीशचंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा की भी लॉन्चिंग हो गई है। मायावती ने उनके कामकाज की प्रशंसा भी की।

उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से लेकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों तक की चहल-पहल दिखने लगी है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो बहिन मायावती ने मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कई राजनैतिक संदेश दिए। बहिन मायावती ने अपनी जनसभा में एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करके राजनैतिक विश्लेषकों को हैरान किया तो दूसरी ओर अगले विधानसभा चुनावों में बिना किसी गठबंधन के

हरेन्द्र शर्मा

उतरने की घोषणा भी कर दी है। बसपा के शक्ति प्रदर्शन को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा की बढती ताकत से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। बहिन मायावती ने न केवल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की अपितु यह भी कहा कि यदि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जुमला न साबित हुआ तो वह पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होंगी।

बहिन मायावती अपनी 2007 की रणनीति को अपनाते हुए पुनः सामाजिक न्याय को आधार बनाकर ही चुनावी मैदान में उतरेंगी ऐसा संकेत उनकी रैली से मिलता है। उन्होंने अपनी रैली मे भीड़ जुटा कर यह संदेश दे दिया है कि उनका कोर वोटबैंक जाटव व दलित अभी भी उनके

साथ है, भले ही इस समय उनके पास विधानसभा में केवल एक विधायक और मात्र 9 प्रतिशत वोट है। बहिन मायावती अपनी रैली में भाजपा के प्रति नरम व सपा तथा कांग्रेस के प्रति गरम दिखाई पड़ीं। उन्होंने अपनी रैली में कांग्रेस व सपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान पर नाटकबाजी कर रही है। कांग्रेस ने देश पर आपातकाल लगाकर बाबा साहब के बनाए संविधान का अपमान किया था। कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने केंद्र सरकार में रहने पर उन्हें आयकर और सीबीआई की जांच में फंसाने की कोशिश की ताकि डा. आंबेडकर और कांशीराम के कारवां को रोका जा सके। अब उसी कांग्रेस के लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। सपा पर तीखा हमला बोलते हुए बहिन मायावती ने कहा कि सपा की सराकर में दलितों व पिछड़ों का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ। उन्होंने सपा सरकार की अराजकता पर हमला किया।

बसपा रैली में बहिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद की लॉन्चिंग के साथ-साथ मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता सतीशचंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा की भी लॉन्चिंग हो गई है। मायावती ने उनके कामकाज की प्रशंसा भी की। जातीय समीकरण साधने के लिए सतीशचंद्र मिश्र के अलावा उमाशंकर सिंह को भी मंच पर जगह दी गई।

प्रशंसनीय बात है कि इस रैली की तैयारी बहिन मायावती और उनके कार्यकर्ता बहुत ही शांत व अनुशासित तरीके से कर रहे थे। बसपा व बहिन मायावती अपने वोटर्स के मध्य बहुत समझदारी के साथ संपर्क बनाती हैं और यही कारण है कि उनका वोटबैंक काफी सीमा तक सुरक्षित रहा है; यद्यपि 2017 के बाद जाटव मतदाता में सेंघ लग चुकी है जिसे फिर से भरोसा दिलाकर वापस लाना बहिन जी के लिए एक कठिन चुनौती है। लंबे समय से बहिन जी का नाम तथा आवाज केंद्रीय राजनीति से दूर रहने के कारण दलित राजनीति में चंद्रशेखर 'रावण' जैसे लोगों का उभार हुआ है जो बसपा के परम्परागत वोटबैक पर दावा ठोंक रहे हैं।

बसपा सुप्रीमो ने भले ही जोर देकर कहा है कि आगामी चुनावों में प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाएगी किंतु यह फिलहाल संभव नहीं प्रतीत हो रहा हें क्योकि बसपा का जो राजनैतिक समीकरण हे उस आधार पर उन्हें सत्ता प्राप्त करने के लिए कम कम के कम 30 प्रतिशत मतों की आवश्यकता होगी और वह अभी मात्र 9 प्रतिशत ही है। प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों में बसपा कार्यकताओं की धरातल पर कड़ी मेहनत के बाद यह मत प्रतिशत 15-20 पहुँच सकता है।

बहिन जी ने खुले मंच से जिस प्रकार से योगी जी की प्रशंसा की वह बसपा के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है क्योंकि संभव है इससे प्रदेश का मुस्लिम मतदाता सपा गठबंधन के साथ जाना पसंद करे।

भले ही बसपा नेत्री मायावती का 2027 में अपने बलबूते पर सरकार में आने का दावा अतिशयोक्ति हो किन्तु इससे 2027 में सपा-बसपा गठबंधन की चचाओं को विराम लग गया है। साथ ही बहिन जी के दावे से सपा गठबंधन के लिए गहरा तनाव और भाजपा के लिए राहत की सूचना आ गई है।

बहिन मायावती ने अपनी जनसभा में एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करके राजनैतिक विश्लेषकों को हैरान किया तो दूसरी ओर अगले विधानसभा चुनावों में बिना किसी गठबंधन के उतरने की घोषणा भी कर दी है। बसपा के शक्ति प्रदर्शन को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा की बढती ताकत से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है।

बिहार में चुनाव, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ?

चुनाव आयोग ने बिहार में दो चरणों में मतदान कराने की घोषणा कर दी है। 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तथा परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों कमर कस चुके हैं। दोनों गठबंधन में टिकट के बंटवारे का मामला अभी सुलझा नहीं है लेकिन दोनों ही ताल ठोंक रहे हैं। नीतीश कुमार जो राजद को हराकर मुख्यमंत्री बने, एक बार फिर युद्ध के मैदान में हैं। एनडीए गठबंधन ने उन्हें ही अपना मुख्यमंत्री फेस चुना है, जबकि महागठबंधन में उहापेह है और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा सिर्फ वही हैं।

इसके पहले राहुल गांधी ने बिहार के दौरे में कहा था कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव को यह बात मंजूर नहीं थी और उन्होंने तुरंत ही अपने नाम की घोषणा कर दी। एक ओर जहां एनडीए गठबंधन में तारतम्य दिखता है, महागठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने अपने बिहार दौरे में कांग्रेसियों को अति उत्साहित कर दिया और उन्हें आगे बढ़ा दिया है, लेकिन सारा खेल लालू यादव पर निर्भर है और वह जाहिर है कि कांग्रेस को ज्यादा तरजीह नहीं देंगे। इस बार उसे सीटें भी कम देंगे। राहुल गांधी का दौरा हमेशा की तरह आरोप-प्रत्यारोप का रहा और उन्होंने चुनाव आयोग पर तमाम तरह के हमले किए और वोट चोरी का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी में साथ दिया है। हालांकि उन्होंने जितने प्रमाण दिए, वे सभी खोखले थे और उनमें कोई दम नहीं था। बिहार में मतदाता सूची पुनर्रीक्षण (एसआईआर) की उन्होंने जमकर आलोचना की और उनके दो वकील सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। इतना ही नहीं तथाकथित चुनाव विशेषज्ञ योगेन्द्र यादव भी अपनी विद्वता झाड़ते हुए कोर्ट में पेश हो गए, लेकिन इनमें से कोई भी वोट चोरी या सूची में गड़बड़ी की बात साबित नहीं कर सका। महज शोर मचाने और पब्लिसिटी करने के अलावा उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि मतदाता सूची बनाने वाले कर्मी राज्य सरकारों के ही कर्मी होते हैं। बीएलओ और एसडीएम, ये सभी राज्य सरकार के कर्मी ही होते हैं, ऐसे में मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप हास्यास्पद है।

नीतीश कुमार जो राजद को हराकर मुख्यमंत्री बने, एक बार फिर युद्ध के मैदान में हैं। एनडीए गठबंधन ने उन्हें ही अपना मुख्यमंत्री फेस चुना है, जबकि महागठबंधन में उहापेह है और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा सिर्फ वही हैं।

यह बात अखिलेश यादव ने भी कही थी कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के लिए बीएलओ और एसडीएम को जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन राहुल तो राहुल हैं, राजकुमार हैं। उन्होंने जो कह दिया वह कह दिया। एटम बम के नाम पर सुतली बम भी फोड़ दिया। इन सबका जनता पर कोई असर होता नहीं दिखा। वह पहले की तरह उदासीन रही। हां, बांग्लादेश से आकर बिहार में बस गए बांग्लादेशियों में खलबली जरूर मच गई। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मतदाता सूची के शामिल होने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज में आधार को भी शामिल कराके उनकी चिंता काफी हद तक दूर कर दी। इसके बाद चुनाव आयोग ने सूची तैयार कर दी है जिस पर महागठबंधन ने कोई खास आपत्ति नहीं जताई है लेकिन कुछ बातें जरूर कही हैं। अगर वे चुनाव हार गए तो फिर यह मुद्दा जोर-शोर से उठाएंगे। बहरहाल बिहार में काफी सरगर्मी दिखती है। लेकिन यह ऊपर ही ऊपर है। यानी मीडिया भर तक ही सीमित है। लोग अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं। कई इलाकों में भरपूर बारिश न होने के कारण धान की बुआई नहीं हो पाई है, वहां के लोग निराश हैं। बाकी शहरों और कस्बों में राहुल गांधी के भाषणों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यहां वोट चोरी बहुत मामूली बात होती थी और बूथ लूटने का भी कल्चर था।

कई जगहों में गरीबों तथा दलितों को वोट देने से रोक भी लिया जाता था। लेकिन अब इंटरनेट और सीसीटीवी कैमरों के कारण हालात बहुत बदल गए हैं। आम बिहारी बहुत ही जागरूक, सजग और समझदारी वाली बातें करने वाला होता है। भारत के किसी भी राज्य में राजनीतिक रूप से इतने जागरूक लोग नहीं मिल सकते। उन्हें हर

चीज का ज्ञान है और इन्सायक्लोपीडिया की तरह वे अतीत की तमाम बातें बता सकते हैं। उनमें तर्क करने की अद्भुत क्षमता है जो आप यूटयूब या टीवी चैनलों पर साफ देखते होंगे। ऐसे में उसे बातों में फंसाना मुश्किल है। राहुल गांधी को यह बात मालूम नहीं थी, इसलिए वह कुछ भी आरोप लगाते रहे। राहुल गांधी यह भी भूल गए कि बिहार में 15 वर्षों के शासन में आरजेडी ने कैसे जंगल राज बना दिया। उनकी ही पार्टी के नेता गाल फाड़-फाडकर चिल्लाते रह गए, लेकिन आलाकमान ने कुछ नहीं सुना। नीतीश कुमार अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनके पास राजनीतिक चालें हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि वह एनडीए का हिस्सा है जिसका नेतृत्व नरेन्द्र मोदी के पास है। पीएम मोदी हाल में पांच बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने दर्जनों तरह की सौगात जनता को दी है। जनता उनसे खुश है क्योंकि वहां नई रेलगाड़ियों से लेकर कई तरह की और सुविधाएं दी गई हैं।

उधर नीतीश कुमार महिलाओं के लिए 10000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दे रहे हैं। जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.21 करोड़ महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जानकारों का मानना है कि यह योजना भारत के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं की ही तरह है और इसका गहरा असर चुनाव में दिखाई पड़ेगा। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है और इस तरह की कोई भी आर्थिक योजना जो तत्काल राहत देती है, लोकप्रिय हो जाएगी। बिहार के लोग करोड़ों की संख्या में पलायन तो कर गए, लेकिन आज भी वह अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि राज्य का विकास हो और नई पीढ़ी को पलायन की त्रासदी न झेलनी पड़े। इसका सीधा हल विकास तथा रोजगार है। जात और जमात की राजनीति इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। जो पार्टियां इस तरह की राजनीति करेंगी, वे इस चुनाव में उसका परिणाम झेल लेंगी। हर बिहारी चाहता है कि उसका राज्य सशक्त और संपन्न हो। ऐसे में इसका असर चुनाव पर पड़ेगा ही। देखते हैं कि जनता कौनसे गठबंधन को चुनती है।

बिहार चुनाव: मुद्दों एवं मूल्यों से दूर भागती राजनीति

वैसे तो हर एक का जीवन अनेकों विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरा रहता है। हमारा हर दिन भी कई विरोधाभासों के बीच बीतता है। आज तो हमारी सारी नीतियों में, हमारे सारे निर्णयों में, हमारे व्यवहार में, हमारे कथन में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित है।

बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। हर दल अपने-अपने घोषणापत्र, नारों और वादों के साथ जनता को लुभाने में जुटा है। मंचों पर भाषणों की गरमी है, प्रचार रथ दौड़ रहे हैं, लेकिन इस शोर में सबसे बड़ी कमी है- जनता के असली मुद्दों की आवाज। राजनीति का यह शोर विकास की असली जरूरतों को दबा रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, और सामाजिक पिछड़ापन अब भी विकराल रूप में मौजूद हैं, वहां चुनावी विमर्श का इनसे विमुख होना चिंताजनक है। यह लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव का विरोधाभास ही नहीं, दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों बिहार चुनाव में कोई भी दल उन मुद्दों को ईमानदारी से नहीं उठा रहा जो सीधे-सीधे जनता के जीवन से

कपिल शर्मा

जुड़े हैं? क्यों शराबबंदी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, अपराध-माफिया शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे वास्तविक सवाल राजनीतिक एजेंडे से गायब हैं?

बिहार में शराबबंदी एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रहा है। यह मुद्दा केवल कानून का नहीं, बल्कि नैतिकता, सामाजिक सुधार और जनजीवन की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। शराबबंदी की सफलता या विफलता को लेकर जनता के मन में अनेक प्रश्न हैं, क्योंकि इस नीति ने जहां कई परिवारों को विनाश से बचाया, वहीं भ्रष्टाचार, अवैध तस्करी और पुलिसिया मनमानी को भी जन्म दिया। दिलचस्प यह है कि इस बार के चुनाव में लगभग सभी प्रमुख दल इस मुद्दे से दूरी बनाए हुए हैं। एनडीए खेमे के नेता खुलकर इस पर बोलने से बच रहे हैं। केवल प्रशांत कुमार जैसे कुछ नेता हैं जो पूर्ण शराबबंदी की पुनः स्थापना का नारा उठा रहे हैं। यह सवाल उठता है, अगर शराबबंदी सचमुच जनता के हित में थी, तो सत्ता पक्ष इससे डर क्यों रहा है? क्या यह स्वीकारोक्ति है कि कानून तो बनाया गया, लेकिन उसका क्रियान्वयन असफल रहा? शराबबंदी क्यों जरूरी है, उस महिला से पूछिये, जिसकी बिछुए शराब पीने से लिये उसके पति ने बेच दी। ऐसी त्रासद घटनाएं बिहार के जन-जन में देखने को मिलती है।

वैसे तो हर एक का जीवन अनेकों विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरा रहता है। हमारा हर दिन भी कई विरोधाभासों के बीच बीतता है। आज तो हमारी सारी नीतियों में, हमारे सारे निर्णयों में, हमारे व्यवहार में, हमारे कथन में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित है। लेकिन बिहार चुनाव ऐसे विरोधाभास के कारण कथनी करनी के अंतर का अखाड़ा ही बनते हुए प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में सत्य खोजने से भी नहीं मिलता। राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों का व्यवहार दोगला हो गया है। उनके द्वारा दोहरे मापदण्ड अपनाने से हर नीति, हर निर्णय समाधानों से ज्यादा समस्याएं पैदा कर रहे हैं। चुनाव एवं चुनावी मुद्दें समस्याओं के समाधान का माध्यम बनने चाहिए, लेकिन वे समस्याओं को बढ़ाने का जरिये बनते रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला-सुरक्षा, अपराध-नियंत्रण की प्राथमिकता के नारे हमारे लिए स्वप्न ही बने हुए हैं।

ये तो कुछ नमूने हैं जबकि स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी हमें अहसास नहीं हो रहा है कि हम स्वतंत्र हैं। राजनीतिक विरोधाभासों और विसंगतियों से उत्पन्न समस्याओं से हम आजाद नहीं हुए हैं। हमारे कर्णधारों के चुनावी भाषणों में आदर्शों का व्याख्यान होता है और कृत्यों में भुला दिया जाता है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि हम हर स्तर पर वैश्वीकरण व अपने को बाजार बना रहे हैं। अपने को, समय को पहचानने वाला साबित कर रहे हैं। पर हमने अपने आप को, अपने भारत को, अपने बिहार को, अपने पैरों के नीचे की जमीन को नहीं पहचाना। नियति भी एक विसंगति का खेल खेल रही है। पहले जेल जाने वालों को कुर्सी मिलती थी, अब कुर्सी पाने वाले जेल जा रहे हैं। यह नियति का व्यंग्य है या सबक? पहले नेता के लिए श्रद्धा से सिर झुकता था अब शर्म से सिर झुकता है। जिन्दा कौमें पांच वर्ष तक इन्तजार नहीं करतीं, हमने 15 गुना इंतजार कर लिया है। यह विरोधाभास नहीं, दुर्भाग्य है, या सहिष्णुता कहें? जिसकी भी एक सीमा होती है, जो पानी की तरह गर्म होती-होती 50 डिग्री सेल्सियस पर भाप की शक्ति बन जाती है। बिहार इस नियति से कब मुक्त होगा, यही इस चुनावों में विमर्श का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए।

बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी बेरोजगारी है। लाखों युवाओं के पास न काम है, न अवसर। हर चुनाव में इस पर वादे किए जाते हैं, लेकिन परिणाम लगभग शून्य रहते हैं। प्रदेश के नौजवान पलायन को मजबूर हैं, मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। चुनावी सभाओं में नौकरियों का झांसा तो मिलता है, लेकिन ठोस योजनाएं और नीतियां कहीं दिखाई नहीं देतीं। राजनीतिक दलों के पास न तो रोजगार सृजन की दीर्घकालिक योजना है, न शिक्षा और कौशल विकास को जोड़ने की कोई ठोस रणनीति। चुनावी भाषणों में 'बिहार के विकास' की बातें होती हैं, लेकिन युवा भविष्य की वास्तविक चिंता कहीं नहीं झलकती। बिहार में महिला सुरक्षा, अपराध और माफिया तंत्र का प्रश्न भी उतना ही ज्वलंत है। हाल के वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। भूमि विवादों, रंगदारी और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों की गतिविधियाँ अब भी जारी हैं। मगर किसी भी दल की ओर से इन पर कोई ठोस नीति या वचन नहीं दिखाई देता।

राजनीतिक दल जानते हैं कि इन विषयों पर बात करना असुविधाजनक है, क्योंकि यह सीधा शासन व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। इसलिए वे इन पर मौन साधे हुए हैं। अपराध और महिला सुरक्षा पर चुप्पी बताती है कि सत्ता प्राप्ति की होड़ में संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं बची है। बिहार की राजनीति आज भी जातीय समीकरणों और तुष्टिकरण की जकड़ में फंसी हुई है। विकास और सुशासन की बातें केवल नारों तक सीमित हैं। उम्मीदवार चयन से लेकर प्रचार तक, हर जगह जातीय गणित प्राथमिकता में है। परिणाम यह है कि मुद्दे हाशिये पर चले जाते हैं और वोट बैंक की राजनीति सर्वोच्च स्थान पा लेती है। विकास के नाम पर किए गए बड़े-बड़े दावे चुनाव बीतते ही धुंधले पड़ जाते हैं। गांवों में आज भी सड़कें टूटी हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, और प्रशासनिक तंत्र भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। ऐसे में जब राजनीतिक दल मुद्दों पर संवाद करने के बजाय केवल आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त हों, तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ना स्वाभाविक है।

आज बिहार को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो चुनाव को जन-कल्याण के दृष्टिकोण से देखे, न कि केवल सत्ता प्राप्ति की दौड़ के रूप में। शराबबंदी, रोजगार, अपराध-मुक्ति, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे बिहार राज्य की आत्मा हैं। इन्हें नजरअंदाज करना, बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेलने जैसा है। विकास का अर्थ केवल सड़कें और पुल नहीं, बल्कि मानव विकास है, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित, शिक्षित, रोजगारयुक्त और सम्मानजनक जीवन जी सके। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनता अब केवल नारों से नहीं, परिणामों से प्रभावित होती है। बिहार चुनाव हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या राजनीति अब केवल सत्ता का खेल बनकर रह गई है? क्या लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनसेवा-अब खो गया है? जब जनता के असली मुद्दे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय, चुनावी भाषणों से गायब हो जाएं, तब यह लोकतंत्र के क्षरण का संकेत है।

जरूरत है कि राजनीतिक दल फिर से उन बुनियादी प्रश्नों पर लौटें, जिन पर बिहार का वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो बिहार की जनता का यह चुनाव एक बार फिर केवल चेहरों और गठबंधनों का उत्सव बनकर रह जाएगा, जहाँ जनहित और जनसरोकार फिर से पीछे छूट जाएंगे। बिहार को नारों नहीं, नीतियों की राजनीति चाहिए और यह तभी संभव है, जब मुद्दों पर बात करने का साहस राजनीति में लौट आए।

राफेल से उड़ान भरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास

राष्ट्रपति ने उड़ान के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए आगंतुक पुस्तिका में लिखा- 'राफेल विमान में उड़ान भरना मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है। इससे मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमता पर गर्व की नई अनुभूति हुई है।'

ब्रिज पंवार

भारत की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। यह वही अंबाला एयरबेस है, जहां फ्रांस से आए राफेल विमानों की पहली खेप उतरी थी। लगभग 30 मिनट तक चली इस उड़ान में राष्ट्रपति ने करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की, जो 15,000 फीट की ऊँचाई और लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर संपन्न हुई। विमान को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गहाणी ने संचालित किया।

राष्ट्रपति ने उड़ान के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए आगंतुक पुस्तिका में लिखा– 'राफेल विमान में उड़ान भरना मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है। इससे मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमता पर गर्व की नई अनुभूति हुई है।' इस प्रकार, यह केवल एक प्रतीकात्मक उड़ान नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, सामरिक शक्ति और नागरिक गर्व का सशक्त संदेश थी।

हम आपको बता दें कि राफेल भारत की सामरिक शक्ति का आधुनिक प्रतीक है। 4.5 पीढ़ी का यह मल्टीरोल लड़ाकू विमान वायुसेना की परिचालन क्षमता को कई गुना बढ़ाता है। राष्ट्रपति का राफेल में उड़ान भरना एक औपचारिक या औपचारिकता-भर कदम नहीं, बल्कि यह संकेत है कि राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति देश की रक्षा तैयारियों पर पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रहा है।

भारत की राष्ट्रपति, जो संवैधानिक रूप से सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, उनका ऐसे लड़ाकू विमानों में उड़ान भरना सैन्य बलों के मनोबल को बढ़ाता है। साथ ही यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने रक्षात्मक ढाँचे को लेकर न केवल सजग है, बल्कि उस पर गर्व भी करता है।

राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान में राष्ट्रपति की उपस्थिति से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी यह संदेश जाता है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और वायु सामर्थ्य के मामले में किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं है।

इसके अलावा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व स्वयं में संघर्ष, सादगी और उपलब्धि का प्रतीक है। ओडिशा के एक छोटे आदिवासी परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुँचना अपने आप में प्रेरक कथा है। जब वह सुखोई-30 एमकेआई (2023) के बाद अब राफेल जैसे उच्च तकनीकी लड़ाकू विमान में उड़ान भरती हैं, तो यह दृश्य करोड़ों महिलाओं और आदिवासी युवाओं के लिए आत्मबल और आत्मविश्वास का स्रोत बनता है।

विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह संदेश अत्यंत सशक्त है कि राष्ट्र की सुरक्षा, तकनीकी शक्ति और निर्णय क्षमता के क्षेत्र में अब लैंगिक भेद की दीवारें टूट चुकी हैं। एक महिला राष्ट्रपति का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान में उड़ान भरना इस बात का प्रमाण है कि महिलाएँ अब केवल 'संवेदनशीलता' का प्रतीक नहीं, बल्कि 'साहस' और 'संकल्प' की मिसाल भी हैं।

आदिवासी समाज के लिए यह गौरव का क्षण है। दशकों से समाज के हाशिए पर रहे तबकों के लिए यह दृश्य 'राष्ट्रीय मुख्यधारा में समान भागीदारी' की अभिव्यक्ति है। जब देश की सर्वोच्च नेता आदिवासी समुदाय से आती हैं और आधुनिकतम सैन्य तकनीक के बीच आत्मविश्वास से भरी दिखाई देती हैं, तो यह सामाजिक मनोविज्ञान को गहराई से प्रभावित करता है। इससे यह संदेश जाता है कि अब कोई भी पृष्ठभूमि प्रगति और नेतृत्व की राह में बाधा नहीं बन सकती। इसके अलावा, राष्ट्रपति का यह कदम

केवल सैन्य प्रतीक नहीं, बल्कि एक राष्ट्रनैतिक वक्तव्य भी है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति के मार्ग पर विश्वास का उद्घोष है। 'नारी शक्ति' और 'जनजातीय गौरव' को केंद्र में रखकर यह दृश्य भारत के बदलते समाज की नई कहानी कहता है– जहाँ संवैधानिक गरिमा, तकनीकी श्रेष्ठता और सामाजिक समावेशन का संगम दिखाई देता है।

साथ ही, भारतीय वायुसेना के लिए यह अवसर आत्मगौरव का भी है। एक राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का राफेल में उड़ान भरना वायुसेना के प्रशिक्षण, अनुशासन और तकनीकी दक्षता पर सर्वोच्च विश्वास का प्रमाण है। यह संदेश सैन्य परंपरा की निरंतरता और आधुनिकता के मेल का है– जहाँ संवैधानिक संस्थाएँ और सशस्त्र बल एकजुट होकर राष्ट्र सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू का यह कदम भारत के उन तमाम युवाओं को भी प्रेरित करेगा जो रक्षा सेवाओं में योगदान देने का सपना देखते हैं। जब देश की प्रथम नागरिक स्वयं युद्धक विमान में उड़ान भरती हैं, तो यह युवाओं के भीतर 'कर्तव्य', 'साहस' और 'सेवा' के आदर्श को पुनः जीवंत करता है।

बहरहाल, द्रौपदी मुर्मू का राफेल में उड़ान भरना मात्र एक प्रतीकात्मक घटना नहीं, बल्कि एक युगबोध है। यह उस भारत की कहानी है जो अपनी परंपरा को सम्मान देता है, आधुनिकता को अपनाता है और समावेशन को अपनी शक्ति बनाता है।

यह उड़ान एक संदेश है-

भारत की नारी अब आकाश की सीमा तक पहुँच चुकी है। आदिवासी समाज अब राष्ट्रीय गौरव की धारा में अग्रणी है और भारत की सुरक्षा व संप्रभुता पर देश का सर्वोच्च नेतृत्व स्वयं प्रहरी बनकर खड़ा है।

यही है नई भारत की उड़ान– आत्मगौरव, समावेश और सामर्थ्य की उड़ान।

संकल्प से सिद्धि की ओर माओवाद का समापन

वर्ष 2014 के पूर्व माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराना अपराध माना जाता था, गरीबों के लिए सरकारी सहायता नहीं पहुच पाती थी और दूर दराज के गांवो से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं हो पाता था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृहमंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने माओवाद को मार्च 2026 तक समाप्त करने का जो संकल्प लिया है वह अब सिद्धि की ओर अग्रसर है। देश का एक बहुत बड़ा भू भाग जो विकास की मुख्यधारा से अलग था अब शेष भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर है। माओवाद का अंत गृहंमत्री अमित शाह के संकल्प व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मन्त्र से ही संभव हो सका है।

आज छत्तीसगढ़ के नक्सवलादी आतंकवाद के लिए कुख्यात बस्तर में तिरंगा फहरा रहा है और

प्रवीण सिंह कुशवाहा

नक्सलवादियों के गढ़ में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभाएं हो रही हैं। गृहमंत्री नक्सलवादियों को स्पष्ट संदेश देते हैं कि, 'माओवादियों आपके पास अब दो ही विकल्प बचे हैं या तो समर्पण कर दें या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार रहें'। इस सख्ती का ही असर है कि 17 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ में एक साथ 210 माओवादियों ने समर्पण किया है।

उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष छह करोड़ रुपए के इनामी माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लेजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू उर्फ अभय ने 60 साथियों सहित बंदूक छोड़कर विकास कि राह थाम ली है। इन माओवादियों ने 54 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है जिनमें सात एके 47 और नौ इंसास राइफलें है। भूपति माओवादी संगठन में सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में माना जाता था और उसने लंबे समय तक महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर अभियानों का नेतृत्व किया। भूपति वही खतरनाक माओवादी आतंकवादी है जिसने छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 76 जवानों का

नरसंहार किया था।

महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला दशकों से माओवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र के शीर्ष माओवादी का समर्पण शेष बचे हुए नक्सलियों खासकर निचले स्तर के कैडर को सीधा संदेश दे रहा है कि अब जब उनका सबसे बड़ा और अनुभवी नेता हथियर डाल रहा है तो उनके पास भागने या छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इससे वे भी समर्पण करने के लिए मन बनायेंगे। यह समर्पण छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए शांति का बड़ा संकेत है। भूपति व उसके साथियों के समर्पण करने से माओवादियों की सबसे मजबूत दीवार ढह गई है।

जनवरी 2023 में गृहमंत्री अमित शाह ने माओवाद के खिलाफ ऑपरेशन को हरी झंडी दी, उसके बाद से अब तक सुरक्षाबलों ने 312 माओवादियों को मार गिराया है। मारे गए माओवादियों में में सीपीआई माओवादी महासचिव वासव राजू समेत पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के आठ सदस्य भी शामिल हैं। 21 जनवरी 2024 से लेकर अब तक माओवाद के खिलाफ अनेक ऑपरेशन सफलतापूर्वक चलाए जा चुके हैं, जिनमें 836 माओवादी गिरफ्तार किये गए हैं और 1639 आत्मसमपर्ण कर चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में पोलित ब्यूरो और एक केंद्रीय समिति सदस्य शामिल है।

वर्ष 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने माओवाद को भारत की सबसे बड़ी चुनौती बताया था किंतु उस समय राजनैतिक कारणों से माओवाद के पूर्ण सफाए का कोई ब्लूप्रिंट नहीं बन पाया था। मनमोहन सरकार के कार्यकाल में माओवादी बहुत बड़ी चुनौती थे। यह लोग नेपाल के पशुपतिनाथ से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक लाल कारिडोर बनाने का सपना देख रहे थे। यह लोग भारत, भारत के संविधान और भारत कि सनातन संस्कृति से बैर रखते हैं। इनको सशक्त राष्ट्र नहीं चाहिए।

वर्ष 2013 में विभिन्न राज्यों के 126 जिलों के माओवादी हिंसा से ग्रस्त होने की रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई थी। वर्ष 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से मार्च 2025 तक यह संख्या 126 से घटकर केवल 18 जिलों तक सीमित रह गई है। वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 11 रह गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के सात जिले, झारखंड का एक जिला पश्चिम सिंहभूम, मध्यप्रदेश का एक जिला बालाघाट, महाराष्ट्र का एक जिला गढ़ चिरौली

और ओडिशा का एक जिला कंधमाल शामिल है। इनमें भी अब छत्तीसगढ़ के तीन जिले बीजापुर, नाराणपुर और सुकमा ही अति माओवादी प्रभावित बचे हैं।

वर्ष 2014 के पूर्व माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराना अपराध माना जाता था, गरीबों के लिए सरकारी सहायता नहीं पहुच पाती थी और दूर दराज के गांवो से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं हो पाता था।

अब समय बदल चुका है, छत्तीसगढ़ के माओवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में विकास की नई गंगा बह रही है। बस्तर जैसे कुख्यात जिले मे तिरंगा शान से फहरा रहा है। युवा बड़ी संख्या में खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहे है। माओवादियों से मुक्त हुए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास किया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं जिससे वहां की जनता दोबारा माओवादियों के दुष्प्रचार में न फंसे। माओवाद के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत उनकी फंडिग को रोकने का काम भी किया जा है।

जैसे-जैसे माओवाद के सफाए का अभियान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके समर्थक राजनैतिक तत्वों के पेट मे दर्द भी उठ रहा है। माओवाद के समर्थन से फल फूल रहे वामपंथी दलो ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बंद करने की अपील तक कर दी। तेलंगना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तो एक कार्यक्रम में कह दिया कि, 'माओवाद एक विचारधारा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर भी माओवादी विचारधारा के समर्थकभी यही बात कह रहे हैं कि यह विचारधारा पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती।

माओवाद एक जहरीली, खतरनाक और नरसंहार का समर्थन करने वाली विचारधारा है जिसका अंत करने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा बल आक्रामक भी हैं और समर्पण करने वालों का स्वागत भी कर रहे हैं। पुनर्वास और पुनर्जीवन का प्रयास कर रही है। विकास को हर द्वार तक ले जा रही है जिससे आम व्यक्ति नक्सल के लाल आतंक के भय को भूल कर आगे बढ़ सके।

पंचायतों तक पहुंची डिजिटल क्रांति, सबको मिलेगा फायदा

देशभर की 12800 से अधिक ग्राम पंचायतों ने इस नवाचारी उपकरण का प्रयोग करते हुए 21000 से ज्यादा वीडियो-आधारित कार्यवत्त अपलोड किए। इस अवसर पर त्रिपुरा की लगभग सभी 1193 ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों ने 'सभासार' को अपनाकर सफलता का नया उदाहरण प्रस्तुत किया वहीं अन्य राज्यों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

हाल में विशाखापत्तनम में ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा में जमीनी स्तर की पहलों के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (एनएईजी) 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के लिए 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चार ग्राम पंचायतों को सेवा वितरण को गहन बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में जमीनी स्तर

संजय बैंसला

की पहल श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। इनमें से दो ग्राम पंचायतों की मुखिया महिलाएं हैं।

डिजिटल विभाजन केवल तकनीक तक पहुंच की कमी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, लैंगिक मानदंडों और डिजिटल साक्षरता के अंतरालों में गहराई से निहित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेताओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें डिजिटल बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच भी शामिल है, लेकिन पिछले एक दशक में मोदी सरकार के डिजिटल क्रांति के

निरंतर आ'न ने इस तस्वीर को बदल दिया है, जिसका परिणाम इन पुरस्कारों के रूप में सामने आया है। विजेता पंचायतों ने डिजिटल शासन, पारदर्शिता और सहभागी सेवा वितरण में नए मानक स्थापित किए हैं। स्वर्ण पुरस्कार विजेता महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत पूरी तरह से पेपरलेस ई-आफिस प्रणाली अपनाने वाली राज्य की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। यह पंचायत 1,027 आनलाइन सेवाएं प्रदान करती है और शत-प्रतिशत घरेलू डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करती है। तत्काल शिकायत निवारण और एसएमएस के माध्यम से सूचना पहुंचाने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक शासन के निर्णयों से जुड़ा रहे।

वहीं रजत पुरस्कार विजेता त्रिपुरा की पश्चिमी मजलिशपुर ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर-आधारित पंचायत शासन के एक माडल में तब्दील हो गई है। यहां जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाणपत्र, व्यापार लाइसेंस, संपत्ति रिकार्ड और मनरेगा जाब कार्ड जैसी सेवाएं आनलाइन उपलब्ध हैं। हर अनुरोध की डिजिटल निगरानी की जाती है, जिससे जवाबदेही, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। जूरी पुरस्कार प्राप्त गुजरात की पलसाना ग्राम पंचायत ने क्यूआर/यूपीआइ-आधारित संपत्ति कर भुगतान, आनलाइन शिकायत निवारण और पारदर्शी कल्याणकारी वितरण को सक्षम करने के लिए डिजिटल गुजरात और ग्राम सुविधा जैसे पोर्टलों को एकीकृत किया है। दूसरी जूरी पुरस्कार विजेता ओडिशा की सुआकाटी ग्राम पंचायत ने ओडिशा वन और सेवा ओडिशा प्लेटफार्मों के माध्यम से आवश्यक सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है, जिससे नागरिकों को 24 घंटे अपडेट मिल रहा है। यह दशार्ता है कि कैसे तकनीक सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को पाटती है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में शामिल जटिलताओं को कम करने के लिए ई-ग्रामस्वराज लांच किया गया। आज पंचायत निर्णय एप के माध्यम से ग्राम सभा बैठकों सहित पंचायतों की बैठकों का प्रबंधन किया जा रहा है। ग्राम सभाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एप में प्रविधान किया गया है, ताकि जब भी ग्राम सभा की बैठक निर्धारित की जाए या पंचायत द्वारा पंचायत निर्णय पोर्टल या मोबाइल एप पर बैठक का एजेंडा या मिनट अपलोड किया जाए, तो एप उपयोगकर्ता समस्त जानकारी को सहजता से प्राप्त कर सकें।

कई राज्यों में पंचायतें अब इलेक्ट्रानिक तरीके से जन्म, मृत्यु, आय, विवाह, निवास प्रमाण पत्र जारी करने, निर्माण और व्यापार की अनुमति तथा संपत्ति और गृह कर आदि का भुगतान जैसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रानिक तरीके से सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित सर्विसप्लस एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं।

हाल में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू सभासार इसकी डिजिटल यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। एआइ और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित यह स्मार्ट टूल ग्राम सभा और पंचायत बैठकों की आडियो/वीडियो रिकार्डिंग से मिनटों में सुव्यवस्थित मीटिंग का सारांश तैयार करता है। बीते 15 अगस्त को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में सभासार का उपयोग उल्लेखनीय और उत्साहजनक रहा, जब देशभर की 12,800 से अधिक ग्राम पंचायतों ने इस नवाचारी उपकरण का प्रयोग करते हुए 21,000 से ज्यादा वीडियो-आधारित कार्यवृत्त अपलोड किए। इस अवसर पर त्रिपुरा की लगभग सभी 1,193 ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों ने सभासार को अपनाकर सफलता का नया उदाहरण प्रस्तुत किया, वहीं अन्य राज्यों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

सभासार 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह बहुभाषी नवाचार विविध भाषाई क्षेत्रों की पंचायतों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करता है। साथ ही ग्राम पंचायतों में भागीदारी लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने, निर्णय प्रक्रिया के पारदर्शी दस्तावेजीकरण और तत्पश्चात कार्रवाई में गति सुनिश्चित करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। यह पहल पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर स्थानीय स्व-शासन और उत्कृष्ट सेवा प्रदायगी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करती है और अमृत काल में जमीनी लोकतंत्र को और सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

गाजियाबाद को हरित, स्मार्ट और नागरिक अनुकूल शहर बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं डीएम रविंद्र कुमार मंदार

देश की राजधानी दिल्ली से सटे और एनसीआर के प्रमुख नगरों में शामिल गाजियाबाद पर हर खास-ओ-आम की पैनी नजर रहती है। इसी के साथ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यकलाप पर भी देशभर के लोगों की निगाहें लगी होती हैं। आलम यह है कि यहाँ के कई प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यकलाप देश के दूसरे शहरों के अधिकारियों के लिए भी नजीर बन गए हैं। वर्तमान में गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार मंदार का नाम भी ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की सूची में शामिल है जिन्हें देखकर दूसरे अधिकारियों को भी प्रेरणा मिलती है।

ललित कुमार

गाजियाबाद के डीएम के रूप में 25 जुलाई 2025 को प्रशासनिक सख्ती और विकास के नए विजन के साथ शुरू हुआ रविंद्र कुमार मंदार का कार्यकाल अब धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। जनता की समस्याओं के शीघ्र समाधान के साथ ही शहर के विकास को नई दिशा देने के लक्ष्य के साथ रविंद्र कुमार मांदर ने प्रशासनिक मशीनरी को भी सक्रिय मोड में ला दिया है। डीएम मांदर की यह कार्यशैली गाजियाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा बटोर रही है। लोग कह रहे हैं कि जनपद गाजियाबाद की कमान अब एक उजार्वान परिणामोन्मुख अधिकारी के हाथ में है।

यूपीएससी 2013 बैच के आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार मंदार को साल 2015 में फिरोजाबाद के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर पहली नियुक्ति मिली थी। इसके बाद से ही आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। फिरोजाबाद के बाद उन्हें आगरा जैसे अहम शहर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया और तत्पश्चात मथुरा का नगरायुक्त रहने के बाद जिलाधिकारी के रूप में

पहली बार उन्हें मार्च 2021 में रामपुर की कमान सौंपी गई। यहाँ 61 दिव्याँग बच्चों की सर्जरी करवाने और 900 तालाब खुदवाने से डीएम रविंद्र कुमार मंदार की खासी चचाएँ सुनाई दीं थी। जौनपुर और प्रयागराज के डीएम का सफर तय करते हुए जुलाई 2025 में उन्हें एनसीआर के गाजियाबाद जैसे अहम शहर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद में भी डीएम मांदर की कुशल कार्यशैली को बेहद सराहा जा रहा है।

राजस्थान में सिरोही जनपद के मंदार गाँव के मूल निवासी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार को बचपन में क्रिकेट खेलने का शौक था। परंतु अपनी माता जी की इच्छा के कारण उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। रविंद्र कुमार मंदार ने अपने पहले ही प्रयास में 138 रैंक प्राप्त कर यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपने परिवार और गृह जनपद मंदार का नाम रोशन कर दिया। रविंद्र कुमार मंदार यहीं नहीं रुके और आईएएस अधिकारी के तौर पर भी लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। प्रयागराज में हुए महाकुंभ की सफलता के पीछे भी रविंद्र कुमार मंदार की मेहनत ही थी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के डीएम रहे रविंद्र कुमार मंदार ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ को जिस तरह से सफलता पूर्वक मैनेज किया था वह वाकई काबिले तारीफ था। वर्तमान में गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार की प्रशासनिक दक्षता का ही परिणाम है कि उन्हें इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार इंटीग्रेटिड़ ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के जरिये शहर की यातायात व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत पूरे शहर में

78 जगहों पर हाई-डेफिनेशन कैमरे लगाए जा रहे हैं जिससे यातायात को व्यवस्थित करने के साथ ही चालान प्रणाली को भी स्मार्ट बनाया जा सकेगा। डीएम मंदार ने नगर निगम को शहर के जलाशयों की नियमित डी-सिल्टिंग (गाद निकासी) और प्राथमिकता के आधार बरसाती जल संरक्षण के निर्देश भी जारी किए हैं। गंगनहर की सफाई के चलते शहर की जलापूर्ति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर डीएम मंदार ने गाजियाबाद के 20 लाख प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की है।

जिलाधिकारी मंदार ने गाजियाबाद में 'स्मार्ट गाजियाबाद पोर्टल' चालू कर एक नई शुरूआत की है जिससे यहाँ के लोग अपनी शिकायतें आनलाइन दर्ज कर उसकी स्थिति भी जान रहे हैं। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में 'जीरो टोलरेंस' की नीति पर चल रहे गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार यहाँ प्रत्येक सोमवार को जन सुनवाई भी कर रहे हैं और उन्होंने जनपद के सभी विभागों को साप्ताहिक रिपोर्ट देने के निर्देश भी जारी किए हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि डीएम मंदार ने जिला प्रशासन को सिस्टम ड्रिवन और जवाबदेह बनाने का संकल्प लिया हुआ है। अपनी कार्यशैली में सख्ती के साथ ही संवेदनशीलता को समाहित करते हुए जिलाधिकारी मंदार गाजियाबाद को हरित, स्मार्ट और नागरिक अनुकूल शहर बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार की मुख्य प्राथमिकताएं

डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने गाजियाबाद की कमान संभालने के साथ ही अपनी मुख्य प्राथमिकताएं भी मीडिया के साथ साझा कीं थी। डीएम मंदार की मुख्य प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं...

- हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण कर जनता की सुनवाई को सशक्त बनाना।
- आरआरटीएस (दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रैपिड रेल) और जनपद की सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा कर विकास को गति देना।
- अवैध निर्माण और प्रदूषण पर नकेल कसना। साथ ही फ्लडप्लान और अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध जाँच अभियान में तेजी लाना।
- स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के तहत हरित पट्टी और तालाबों को पुनर्जीवित करना।
- उद्योगों को बढ़ावा और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे उद्योगों के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना।

कौन हैं रविंद्र कुमार मंदार?

गाजियाबाद। राजस्थान में सिरोही जनपद के मंदार गाँव के मूल निवासी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार को बचपन में क्रिकेट खेलने का शौक था। परंतु अपनी माता जी की इच्छा के कारण उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। रविंद्र कुमार मंदार ने अपने पहले ही प्रयास में 138 रैंक प्राप्त कर यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपने परिवार और गृह जनपद मंदार का नाम रोशन कर दिया। रविंद्र कुमार मंदार यहीं नहीं रुके और आईएएस अधिकारी के तौर पर भी लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। प्रयागराज में हुए महाकुंभ की सफलता के पीछे भी रविंद्र कुमार मंदार की मेहनत ही थी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के डीएम रहे रविंद्र कुमार मंदार ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ को जिस तरह से सफलता पूर्वक मैनेज किया था वह वाकई काबिले तारीफ था। वर्तमान में गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार की प्रशासनिक दक्षता का ही परिणाम है कि उन्हें इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है।

यूपीएससी 2013 बैच के आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार मंदार को साल 2015 में फिरोजाबाद के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर पहली नियुक्ति मिली थी। इसके बाद से ही आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। फिरोजाबाद के बाद उन्हें आगरा जैसे अहम शहर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया और तत्पश्चात मथुरा का नगरायुक्त रहने के बाद जिलाधिकारी के रूप में पहली बार उन्हें मार्च 2021 में रामपुर की कमान सौंपी गई थी। यहाँ 61 दिव्याँग बच्चों की सर्जरी करवाने और 900 तालाब खुदवाने के बाद से ही डीएम रविंद्र कुमार मंदार की खासी चचाएँ सुनाई देने लगीं थी। जौनपुर और प्रयागराज के डीएम का सफर तय करते हुए जुलाई 2025 में उन्हें एनसीआर के गाजियाबाद जैसे अहम जनपद का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद में भी डीएम मंदार की कुशल कार्यशैली को बेहद सराहा जा रहा है।अपनी कार्यशैली में सख्ती के साथ ही संवेदनशीलता को समाहित करते हुए डीएम मंदार गाजियाबाद को हरित, स्मार्ट और नागरिक अनुकूल शहर बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंगः राष्ट्रपति

अब यूपी के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली में नहीं भटकना होगाः मुख्यमंत्री योगी

YASHODA
MEDICITY
26th October 2025 | Yashoda

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का किया उद्घाटन

- मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना निजी चिकित्सा संस्थानों की होनी चाहिए प्राथमिकता : राष्ट्रपति
- सिकल सेल एनीमिया जैसी जनजातीय क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों पर विशेष फोकस करे अस्पताल : राष्ट्रपति

ललित कुमार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के आधुनिक स्वास्थ्य ढांचे और जनसेवा की भावना की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर उन्हें गर्व और खुशी दोनों का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि यशोदा मेडिसिटी ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा के साथ अपनाया है। कोविड महामारी के दौरान इस संस्थान ने बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भी उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने बताया कि 'सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर (स्टेप्स)' के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र यशोदा मेडिसिटी को बनाया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह संस्थान सिकल सेल एनीमिया जैसी जनजातीय क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों पर विशेष रूप से काम कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यशोदा मेडिसिटी इस दिशा में और अधिक योगदान देगी। अस्पताल के चेयरमैन और एमडी डॉ. पी.एन. अरोड़ा के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने सेल्फ मेड हेल्थकेयर मिशन के तहत एक विश्वस्तरीय संस्थान स्थापित किया है, जो समाज सेवा और राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल को अपनी माता यशोदा जी के नाम पर रखना भारतीय संस्कारों और स्वदेशी भावना का उदाहरण है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने अस्पताल का दौरा भी किया

और कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतना अत्याधुनिक अस्पताल देखा है, जहां एक ही छत के नीचे सभी परीक्षण और उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों का कीमती समय बचता है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और यह तभी संभव है जब देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। उन्होंने कहा कि इस तरह की मेडिसिटी न केवल इलाज के लिए बल्कि अनुसंधान और नवाचार के लिए भी जरूरी हैं।

राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि यशोदा मेडिसिटी आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों के साथ मिलकर कैंसर की जीन थैरेपी जैसी स्वदेशी तकनीकों को अपनाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है और सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान देश के लिए अमूल्य योगदान दे सकते हैं। मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना इन संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

अंत में उन्होंने यशोदा मेडिसिटी से उम्मीद जताई कि यह 'अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस टू ऑल' के मिशन को पूरा करेगी और देश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने डॉ. पी.एन. अरोड़ा और उनकी टीम को शुभकामनाएं दीं कि वे सेवा, गुणवत्ता और नवाचार के साथ देश को गौरवान्वित करते रहें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ पीएन अरोड़ा, सीईओ डॉ उपासना अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

विशेष शॉल भेंट कर हुआ अतिथियों का स्वागत

यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन समारोह में शामिल सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत संस्थान के चेयरमैन और एमडी डॉ पीएन अरोड़ा ने विशेष शॉल भेंट कर किया। शॉल पर रामायण के दृष्यों को रेशम के धागों से उकेरा गया है और प्रत्येक शॉल को बनाने में कारीगरों को एक वर्ष का समय लगा है। इसके साथ ही अतिथियों को शंख और स्मृति चिह्न देकर उनका अभिवादन किया गया।

हर नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा दिलाना डबल इंजन सरकार का लक्ष्यः सीएम योगी

- स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ निवेश और रोजगार का भी माध्यम बन रहा है यह अस्पतालः सीएम
- एक ही छत के नीचे 5000 से अधिक लोगों को एक साथ मिलेगा रोजगारः मुख्यमंत्री
- यशोदा मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री

अनादि शुक्ल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में स्थापित यशोदा मेडिसिटी इसका सशक्त उदाहरण है। यह केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परिभाषा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के माध्यम से न केवल एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को अब दिल्ली में महंगे इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाजियाबाद में ही वर्ल्ड क्लास हेल्थकेयर उपलब्ध हो गया है।

इनवेस्टमेंट भी और रोजगार का माध्यम भी

उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में जब उत्तर प्रदेश में थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई थी, उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इन्वेस्ट यूपी के साथ एमओयू किया था कि गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम से अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करेंगे। इसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा भी, जिसके लिए पहले

प्रदेश और एनसीआर के नागरिकों के लिए हेल्थकेयर को मिली नई दिशा

मुख्यमंत्री ने डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और एनसीआर के नागरिकों के लिए हेल्थकेयर की नई दिशा तय की है। उन्होंने कहा कि डॉ. अरोड़ा का व्यवहार, सेवा भावना और प्रतिबद्धता उन्हें विशिष्ट बनाती है। वे हर जरूरतमंद का इलाज सुनिश्चित करते हैं, चाहे आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी जैसे प्रोजेक्ट न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि रोजगार और विश्वास का नया अध्याय भी लिख रहे हैं। यह अस्पताल उत्तर प्रदेश की उस नई सोच का प्रतीक है, जो स्वास्थ्य, निवेश और सेवा को एक सूत्र में जोड़ती है।

लोगों को विदेश जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि तब यह विश्वास नहीं होता था कि इतनी जल्दी यह संभव होगा, लेकिन डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम ने मात्र तीन वर्षों में इसे साकार कर दिखाया। यह इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी। इस अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य हेल्थकेयर से जुड़े 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन वर्षों में यह जो काम हुआ है वह उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश माहौल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ति को दशार्ता है।

प्रदेश में स्थापित हुए 42 नए मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्षों में हेल्थ सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य में अब तक 42 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि दो एम्स (गोरखपुर और रायबरेली) सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले और हेल्थकेयर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय मनीषा कहती है किह्लशरीरं माध्यमं खलु धर्मसाधनम्ह्व यानी जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही संभव है। उन्होंने कहा कि यशोदा मेडिसिटी इसी भावना को मूर्त रूप देती है। यहां कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो अब तक केवल विकसित देशों में ही मिलती थीं।

राष्ट्रपति जी का जीवन देश के लिए प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी ने शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे की जाती है, यह अपने विराट व्यक्तित्व और कृतित्व से देश की 140 करोड़ आबादी, विशेषकर आधी आबादी के सामने प्रेरणा का स्रोत बनकर दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ जैसे पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित इस पावन अवसर पर वे राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी स्वागत करते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित हर मुद्दे पर सहज भाव से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, यशोदा मेडिसिटी के अध्यक्ष और एमडी डॉ. पीएन अरोड़ा और डॉ उपासना अरोड़ा उपस्थित रहीं।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने लिया है नया रूप : राजनाथ सिंह

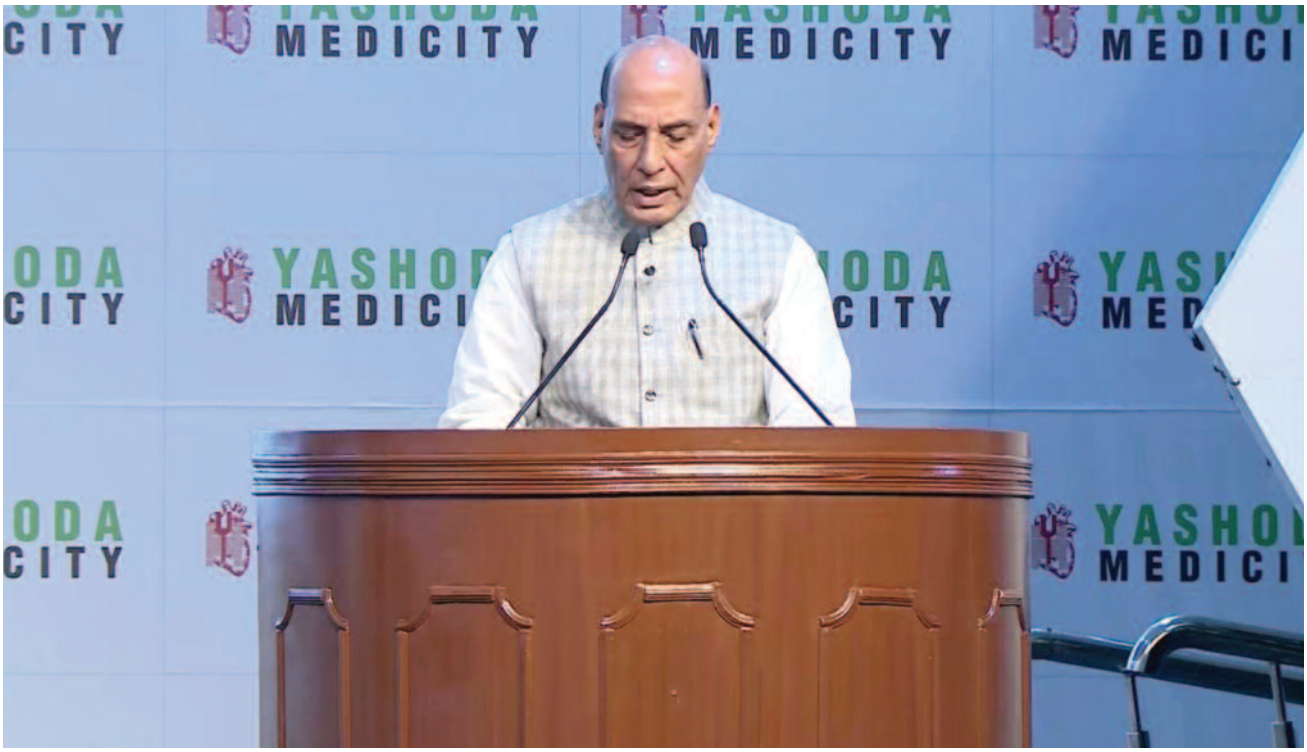

- स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की आधारशिला : रक्षामंत्री
- 2014 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 800 हो गये हैं, एमबीबीएस सीटें केवल 50 हजार थीं, आज यह 1 लाख 20 हजार से ज्यादा हो चुकी हैं : राजनाथ सिंह

अनिल वशिष्ठ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो शक्तिशाली और स्वस्थ हो। हमारा हर कदम, हर नीति, हर प्रयास देश के गरीब, वंचित और ग्रामीण जनमानस को समर्पित है। हम मानते हैं कि जब भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी भारत सशक्त होगा। हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम होना बहुत जरूरी है।

मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्निकल रिसर्च को मिलेगी नई दिशा

राजनाथ सिंह ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी के लिए गौरव की बात है कि इसे दक्षिण एशिया में रोबोटिक्स सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। यह उपलब्धि निश्चित रूप से मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्निकल रिसर्च को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि हम जब भी किसी सफल इंसान की कहानी पढ़ते हैं, आपको यही देखने को मिलेगा कि हर बड़ी यात्रा की शुरूआत किसी न किसी बड़ी व्यक्तिगत पीड़ा से निकलती है। यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉ पीएन अरोड़ा ने 1986 में अपनी माता को कैंसर की वजह से मृत्युशैया पर देखा, उनकी इसी पीड़ा ने यशोदा मेडिसिटी को जन्म दिया। आज यह अस्पताल समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है।

जेनरिक मेडिसिन से गांव-गांव में लोग हो रहे लाभान्वित

रक्षा मंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनता को अत्यंत किफायती दर पर जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज गांव गांव में लोग इन केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही हमने एक मजबूत स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर विशेष बल दिया है। 2014 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे वही आज बढ़कर 800 पहुंच चुकी है। 2014 में एमबीबीएस की सीटें केवल 50 हजार हुआ करती थीं, आज यह 1 लाख 20 हजार से ज्यादा हो चुकी हैं। 22 नये एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसमें से 12 पूरी क्षमता के साथ कार्यरत हैं, बाकियों का निर्माण पूरी तेजी पर हैं। जब ये सभी संस्थान पूरी तरह से कार्यरत होंगी तो हमारा हेल्थ नेटवर्क और मजबूत होगा।

दक्षिण एशिया में नवाचार की नई परिभाषा गढ़ेगी यशोदा मेडिसिटी

अंत में उन्होंने यह कहकर अपनी खुशी जाहिर की कि, यशोदा समूह इस क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि यह संस्था आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया में नवाचार की नई परिभाषा गढ़ेगी। रक्षामंत्री ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने यहां आकर यहां के चिकित्सक और कर्मचारियों के मन में नई ऊर्जा का संचार किया है। राजनाथ सिंह ने यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन और एमडी डॉ पीएन अरोड़ा, सीईओ डॉ उपासना अरोड़ा और उनकी टीम को बधाई दी। ससे पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने यशोदा मेडिसिटी का भव्य उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद रहे।

सरकार एक संरक्षक के रूप में बुजुर्गों के साथ खड़ी है

राजनाथ सिंह ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाह किया है। ठीक उसी प्रकार हम भी समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने नया रूप लिया है। पहले जहां यह गरीब के लिए चिंता का कारण होता था, वही आज उसके अधिकार के रूप में उसके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का कोई गरीब किसी भी बीमारी के कारण अपने जीवन की उम्मीद न खोए। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ परिवारों को हर वर्ष पांच लाख रूपए के स्वास्थ्य बीमा का कवच प्रदान किया गया है। अब 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल किया गया है। ताकि जीवन के उस पड़ाव में जब देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब सरकार एक संरक्षक के रूप में उसके साथ खड़ी रहे।

बोले रक्षा मंत्री, हम उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो स्वस्थ और शक्तिशाली हो

अरुण शर्मा

दवा बनीं जहर मासूमों की गई जान

दो राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत की घटनाएं देश की दवा नियामक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यह केवल एक चिकित्सा त्रुटि या आकस्मिक दुर्घटना नहीं, बल्कि उस तंत्र की विफलता का प्रतीक है जिस पर जनता अपने जीवन की रक्षा के लिए भरोसा करती है। दवा जैसी जीवनदायी वस्तु में भी जब लालच, लापरवाही या भ्रष्टाचार घुसपैठ कर जाते हैं तो वह अमृत भी विष बन जाता है। बच्चों की मासूम जानें जब घटिया या मिलावटी दवा के कारण चली जाती हैं, तो यह केवल परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता एवं विश्वास की मृत्यु होती है। कफ सिरप में पाए गए विषैले तत्व-जैसे डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल, पहले भी कई देशों में सैकड़ों बच्चों की जान ले चुके हैं। फिर भी बार-बार ऐसे हादसे होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की दवा नियामक व्यवस्था में संरचनात्मक खामियां बनी हुई हैं। सवाल है कि पिछली गलतियों से क्या सीखा गया? भारत में बने कफ सिरप पहले भी सवालों में आ चुके हैं। 2022 में गाम्बिया में कई बच्चों की मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने एक भारतीय कंपनी के कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बाद भी कई और जगहों से इसी तरह की शिकायत आई।

दवाओं के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। करीब 200 देशों में यहां से दवाएं निर्यात होती हैं और जेनेरिक दवाएं सबसे ज्यादा यहीं बनती हैं। इन उपलब्धियों के बीच इन दो प्रमुख राज्यों में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत शर्मनाक एवं त्रासदीपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि दवा के क्षेत्र में जिस तरह की निगरानी, मानक और सुरक्षा उपायों की जरूरत है, उसमें कोताही बरती जा रही है। दवा के रूप में जहर धडल्ले से मासूमों की मौत का कारण बन रहा है। इस घटना सामने आने के बाद कार्रवाई का दौर भले ही जारी है। दवाएं वापस ली गई हैं, केस दर्ज हुआ है और नैशनल रेगुलेटर अथॉरिटी ने कई राज्यों में जांच की है। इन घटनाओं से साफ है कि दवा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के स्रोत से लेकर तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जांच तक हर स्तर पर लापरवाही व्याप्त है। कई कंपनियां लागत घटाने के लिए औद्योगिक ग्रेड के सॉल्वेंट या रसायनों का प्रयोग कर लेती हैं जो मानव उपभोग के लिए निषिद्ध होते हैं। वहीं निरीक्षण और परीक्षण की सरकारी व्यवस्था न केवल कमजोर है बल्कि अक्सर प्रभावशाली कंपनियों के दबाव में निष्क्रिय भी हो जाती है। राज्य और केंद्र स्तर के दवा-नियामक विभागों में पर्याप्त संसाधन और तकनीकी क्षमता का अभाव है, जिससे समय पर निगरानी और सैंपल परीक्षण संभव नहीं हो पाता। जब निरीक्षण औपचारिकता बन जाए और रिपोर्टें खरीद-फरोख्त की वस्तु बन जाएं, तब ऐसी

त्रासदियां स्वाभाविक हैं। तमिलनाडु की दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के नमूने में 48.6 प्रतिशत डाई एथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार इसकी मात्रा 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों और मशीनों में होता है। इसकी वजह से पीड़ित बच्चों की किडनी फेल हो गई। इन घटनाओं ने न केवल स्वास्थ्य प्रशासन की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है बल्कि भारत की वैश्विक छवि पर भी धब्बा लगाया है। पिछले वर्षों में अफ्रीकी देशों में भी भारतीय सिरप से हुई मौतों के बाद कई देशों ने हमारे फार्मा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था। अब घरेलू स्तर पर घटित ऐसी घटनाएं यह दशार्ती हैं कि हमने उन हादसों से कोई सबक नहीं लिया। दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवा उत्पादक देश के रूप में भारत को यह मानना होगा कि केवल उत्पादन की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता ही हमारी असली ताकत होनी चाहिए। इस संकट का सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि इसका शिकार वे मासूम बच्चे बने जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई थी और जिनकी जीवन रक्षा का उत्तरदायित्व समाज और राज्य पर है। इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी केवल दोषी कंपनियों पर नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर है जिसने नियमन और नैतिकता की आंखें मूंद लीं। दवाओं में मिलावट या गलत प्रमाणपत्र देना कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ किया गया घोर अपराध है। इस पर कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी निमार्ता या अधिकारी ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचे।

भारत के फार्मास्युटिकल मार्केट का आकार लगभग 60 अरब डॉलर है। इसका बड़ा हिस्सा छोटी कंपनियों के पास है। सीडीएसीओ ने इस साल अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ज्यादातर छोटी और मझोली कंपनियों की दवाएं जांच में तयशुदा मानक से कमतर पाई गईं। इस जांच में 68 प्रतिशत एमएसएमई फेल हो गई थीं। इससे पहले, जब केंद्रीय एजेंसी ने 2023 में जांच की, तब भी 65 प्रतिशत कंपनियों की दवाएं सब-स्टैंडर्ड मिली थीं। प्रश्न है कि यह तथ्य सामने आने के बाद आखिर सरकार क्या सोच कर इन दवाओं को बाजार में विक्रय क्यों जारी रहने दिया? क्यों ऐसे हादसे होने दिये जाते रहे? यह आवश्यक है कि दवा उद्योग में कच्चे माल की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाए, हर बैच की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और दवाओं के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों। केंद्र और राज्य सरकारों को ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हर कंपनी के लाइसेंस नवीनीकरण के समय उसकी पिछली गुणवत्ता रिपोर्ट और परीक्षण परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। जिन कंपनियों ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है, उनके लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए और शीर्ष प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं, बल्कि इन मामलों में आपराधिक जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।

इसके साथ ही चिकित्सा जगत और समाज को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। डॉक्टरों को यह समझना होगा कि शिशुओं को ओटीसी- ऑवर दी कॉउन्टर दवाएं देना कितना खतरनाक हो सकता है। सरकार द्वारा जारी परामर्श और चेतावनियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। मीडिया को भी सनसनी से ऊपर उठकर जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। इन त्रासदियों को केवल समाचार बनाकर भुला देना नहीं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य-सुधार के आंदोलन में बदलना समय की मांग है। क्योंकि सरकारी अनुमान से इस साल देश का दवा निर्यात 30 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। वहीं, 2030 तक फार्मा मार्केट के 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन, इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। दवाओं की जांच और निगरानी अभी तक की कमजोर कड़ी साबित हुई है। केंद्रीय और राज्य की नियामक एजेंसियों को ज्यादा बेहतर तालमेल के साथ, पारदर्शिता, ईमानदारी और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला केवल इकॉनमी या देश की छवि ही नहीं, अनमोल जिंदगियों से जुड़ा है।

अंततः यह घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन रक्षा के साधनों में जब नैतिकता का अभाव हो जाता है तो प्रगति की समूची इमारत ध्वस्त हो जाती है। दवा उद्योग में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी बच्चे की जान किसी घटिया या मिलावटी दवा के कारण न जाए। जब तक दवा बनाने वाला और दवा बांटने वाला अपनी जिम्मेदारी को धर्म, करुणा, विश्वास और ईमानदारी की दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक ऐसी त्रासदियां दोहराई जाती रहेंगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम दवा नहीं, दायित्व बनाएं, नियमन नहीं, निष्ठा पैदा करें और इस मानवता विरोधी अपराध के लिए दोषियों को उदाहरण स्वरूप कठोरतम दंड दें ताकि भविष्य में जीवन रक्षक औषधि फिर से विश्वास की प्रतीक बन सके।

तरक्की को मुंह चिढ़ा रहे हैं महिला अपराधों के आंकड़े

डब्ल्यूपीएस इंडेक्स (महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक) की 2023 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग साल 2023 में 128वें स्थान पर रही। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और स्वीडन शीर्ष पर रहे, जबकि अफगानिस्तान, यमन और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे निचले स्थान पर रहे।

एन के शर्मा

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष 2023 के महिला अपराधों के आंकड़े देश की तरक्की के आंकड़ों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। देश एक तरफ जहां रक्षा, विज्ञान–तकनीकी, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में जहां लगातार आगे बढ़ रहा है वहीं महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में शर्मसार हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में उससे पिछले दो सालों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पूरे देश में ऐसे करीब 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए।

वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में 4,45,256 और 2021 में 4,28,278 मामले थे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 66,381 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,450, पश्चिम बंगाल में 34,691 और मध्यप्रदेश में 32,342 मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना प्रति लाख महिला जनसंख्या पर 124.9 अपराध दर के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि इसके बाद राजस्थान 114.8, ओडिशा 112.4, हरियाणा 110.3 और केरल में 86.1 अपराध दर दर्ज की गई।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले सबसे ज्यादा थे, जिनमें 133,676 मामले दर्ज किए गए और इनकी दर 19.7 रही। महिलाओं के अपहरण और बंधक बनाने के 88,605 मामले दर्ज किए गए और इनकी दर 13.1 रही। महिलाओं की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला करने के 83,891 मामले आए जबकि बलात्कार के 29,670 मामले दर्ज किए गए। अठारह वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं से बलात्कार के 28,821 मामले आए और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से बलात्कार के 849 मामले आए। बलात्कार के प्रयास के 2,796 मामले दर्ज किए गए।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बच्चों से बलात्कार के 40,046 मामले, यौन उत्पीड़न के 22,149 मामले, यौन प्रताड़ना के लिए 2,778 मामले, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने के 698 मामले और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत 513 मामले दर्ज किए गए। पुलिस के निपटारा आंकड़ों से पता चला कि पिछले वर्षों से 185,961 मामले जांच के लिए

लंबित थे, जबकि 4,48,211 नए मामले दर्ज किए गए और 987 स्थानांतरित किए गए। इस तरह कुल 635,159 मामले थे। एसिड अटैक के 113 मामले दर्ज किए गए।

साल 2012 में दिल्ली में निर्भया के बलात्कार और हत्या के बाद जमीन पर ज्यादा कुछ बदला नहीं दिखता। कठोर कानून मौजूद हैं, पर वे कितने प्रभावी हैं? साल 2022 के लिए उपलब्ध आंकड़े दिखाते हैं कि 'महिलाओं के खिलाफ अपराध' के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किये गये, जो साल 2021 से चार फीसदी ज्यादा थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध का सबसे बड़ा हिस्सा 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (31.4 फीसदी) के तहत दर्ज हुआ, जबकि सभी अपराधों में 'शील हनन की नीयत से महिलाओं पर हमले' का हिस्सा 18.7 फीसदी था, और 'बलात्कार' 7.1 फीसदी पर रहा।

डब्ल्यूपीएस इंडेक्स (महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक) की 2023 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग साल 2023 में 128वें स्थान पर रही। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और स्वीडन शीर्ष पर रहे, जबकि अफगानिस्तान, यमन और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे निचले स्थान पर रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में महिलाओं को निशाना बनाकर की जाने वाली राजनीतिक हिंसा के मामले में भारत शीर्ष 10 सबसे खराब देशों में शामिल है। मेक्सिको

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले सबसे ज्यादा थे, जिनमें 133,676 मामले दर्ज किए गए और इनकी दर 19.7 रही। महिलाओं के अपहरण और बंधक बनाने के 88,605 मामले दर्ज किए गए और इनकी दर 13.1 रही।

537 ऐसी घटनाओं के साथ इस सूची में शीर्ष पर है, उसके बाद ब्राजील (327) का स्थान है, जबकि भारत इस सूची में 125 घटनाओं (प्रति 100,000 महिलाओं पर) के साथ सातवें स्थान पर है, जहाँ विशेष रूप से राजनीतिक हिंसा के लिए महिलाओं को निशाना बनाया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) में पाया गया कि 18-49 वर्ष की आयु की 29.3% महिलाओं ने अपने जीवनकाल में पति द्वारा हिंसा का अनुभव किया है। अगर अपराध दर्ज भी हो जाते हैं, तो न्याय धीमा हो सकता है; पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अक्सर पीड़ितों को ही दोषी ठहराते हैं या उनकी गवाही को हतोत्साहित करते हैं। परिणामस्वरूप, कई मामले आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं होते। विशेषज्ञों का कहना है कि सांस्कृतिक शर्मिंदगी और प्रतिशोध का डर रिपोर्ट दर्ज कराने में बड़ी बाधाएँ हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का कारण पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक रूढ़िवादिता, शिक्षा और जागरूकता की कमी, कानूनों का कम प्रभावी कार्यान्वयन और महिलाओं के प्रति समाज की घटती संवेदनशीलता जैसे सामाजिक-आर्थिक और संरचनात्मक कारक हैं। भारत की चुनौती वैश्विक रुझानों के समान और उनसे भी बदतर है। कई देशों की तरह, भारत भी कम रिपोर्टिंग और कलंक से जूझ रहा है। लेकिन गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रह और विशाल जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि अघोषित अपराधों का एक छोटा सा प्रतिशत भी बहुत बड़ी संख्या में तब्दील हो जाता है।

अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना इस बात पर जोर देती है कि समाधानों में हर देश की हिस्सेदारी है - अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने से लेकर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तक। कानूनों और जागरूकता के मामले में भारत में हाल ही में हुए सुधार सकारात्मक हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी कई समकक्षों से पीछे है।

इंसानों की लालची प्रवृत्ति का शिकार बन रहे हैं गजराज

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलीफेंट एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य हाथियों के प्राकृतिक आवासों में उनके लंबे समय तक अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। इसके बावजूद जंगलों के कटने और हाथियों के प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण की रोकथाम के बगैर यह विशाल और महत्वपूर्ण जानवर अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

देश में हाथियों पर चौतरफा संकट मंडरा रहा है। प्राकृतिक आवास सिकुड़ने से गजराज रौद्र रूप इंसानों से संघर्ष के रूप में सामने आ चुका है। देश में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच कुल 2,869 लोगों की मौत हाथियों के हमलों में हुई।

देश में बढ़ती महत्वकांक्षा और लालची प्रवृत्ति ने पर्यावरण के साथी और हिन्दुओं की पूजा के प्रतीक हाथियों को भी नहीं बख्शा है। अन्य वन्यजीवों और वनस्पतियों के तरह अब हाथियों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे है। हाथी मेरे साथी के बजाए अब दुश्मन बनता जा रहा है। वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) की नई जनगणना के मुताबिक पिछले 8 साल के भीतर देश में हाथियों की संख्या करीब 25% तक घट गई है। देश में पहली बार डीएनए के आधार पर हाथियों की गणना में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे तो हुए ही हैं, साथ ही जनगणना डराने वाली भी है। यह रिपोर्ट बताती है कि शिकार की वजह से नहीं बल्कि जंगलों के कम होने और इंसानों के साथ संघर्ष के चलते हाथियों की संख्या में कमी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 22,446 हाथी हैं। जबकि 2017 में देश में हाथियों की संख्या 29,964 के करीब थी।हाथियों की गणना करने के लिए पहली बार डीएनए आधारित प्रणाली को अपनाया है, जबकि 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च होने के बाद से ही तस्वीरों और हाथियों की लीद के आधार पर ही इनकी गिनती होती थी। डब्ल्यू आई आई के वैज्ञानिक और रिपोर्ट के मुख्य लेखक कमर कुरैशी के मुताबिक जंगल कट रहे हैं, हाथियों के आवास सिकुड़ रहे हैं और कॉरिडोर का कनेक्शन खत्म हो रहा है। इस वजह से इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। खासतौर से मध्य भारत और असम में। इस रिपोर्ट में एक अच्छी बात यह सामने आई कि शिकार के लिए हाथियों को नहीं मारा जा रहा है। लेकिन घर आवासों का सिकुड़ना बड़ी चिंता की बात है। भारत में वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा हाथी हैं। यहां 11,934 हाथी हैं, जबकि 2017 में 14,587 हाथी हुआ करते थे। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय इलाकों में हाथियों की संख्या 10,139 से घटकर 6559 हो गई है। मध्य भारत और ईस्टर्न घाट में 3128 से घटकर 1891 हाथी ही रह गए हैं। हाथियों की मौजूदा सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में 6013, असम 4159, तमिलनाडु 3136, केरल 2785, उत्तराखंड 1792 ओर ओडिशा में 912 हाथी मौजूद हैं। झारखंड में जंगली हाथियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है और यह मात्र 217 रह गई है, जोकि

2017 के 678 के आंकड़े से काफी कम है।

देश में हाथियों पर चौतरफा संकट मंडरा रहा है। प्राकृतिक आवास सिकुड़ने से गजराज रौद्र रूप इंसानों से संघर्ष के रूप में सामने आ चुका है। देश में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच कुल 2,869 लोगों की मौत हाथियों के हमलों में हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में सबसे अधिक 624, झारखंड में 474, पश्चिम बंगाल में 436, असम में 383 और छत्तीसगढ़ में 303 लोगों की मौत हाथियों के हमलों में हुई। तमिलनाडु और कर्नाटक में क्रमशः 256 और 160 लोगों की मौत हुई। इसके विपरीत, बाघों के हमलों में 2020 से 2024 के बीच कुल 378 लोगों की मौत हुई। इनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 218 मौतें, उत्तर प्रदेश में 61 और मध्य प्रदेश में 32 मौतें दर्ज की गईं। हर साल करीब 60 हाथियों की भी मौत प्रतिशोध में हो जाती है।

देश की रेल परिवहन व्यवस्था हाथियों के लिए खतरनाक बनी हुई है। पिछले पांच वर्षों में देश भर में रेलगाड़ियों की चपेट में आने से कम से कम 79 हाथियों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में खड़गपुर-टाटानगर रेलखंड पर तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक हथिनी और उसके बच्चे समेत तीन हाथियों की जान चली गई। 7 हाथियों का एक झुंड रेलवे लाइन पार कर रहा था। इसी दौरान एक ट्रेन आ गई जिससे यह बड़ा हादसा हो गया था। खड़गपुर रेल मंडल में आने वाला यह रूट जंगलों से घिरा है। यहां हाथियों के साथ-साथ अन्य जंगली जानवर भी है। हाथियों सहित अन्य जंगली जानवरों की ट्रेन से कटने की ज्यादातर घटनाएं पहाड़ी और जंगली इलाकों में ही होती है।

अवैध शिकार के मामलों में कमी आई है, किन्तु यह अभी भी एक खतरा बना हुआ है। हाथियों की मौत के कुछ मामलों में जहर एक कारण हो सकता है। बिजली के तारों की चपेट में आने से भी हाथियों की मृत्यु होती है। हाथी का महत्व सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक दृष्टिकोण से है।

यह महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है जो कई अन्य प्रजातियों को सहारा देती है। हाथी अपनी सूंड से पानी की खुदाई करते हैं, जो अन्य जानवरों को भी पानी उपलब्ध कराता है। आर्थिक रूप से, हाथी पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और वास्तु में समृद्धि और सौभाग्य लाते हैं। हाथियों के मल से विभिन्न प्रकार के पौधों के बीज फैलते हैं, जो सवाना जैसे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। वे घने जंगलों में रास्ते भी बनाते हैं जो अन्य जानवरों को आने-जाने में मदद करते हैं।

विश्व हाथी दिवस पर वाइल्डलाइफ एसओएस ने भारत में सड़कों पर भीख मांगते हाथियों की दुखद स्थिति को उजागर किया। इन विशालकाय प्राणियों को क्रूरता से सड़कों पर घसीटा जाता है। वाइल्डलाइफ एसओएस का बेगिंग एलीफेंट अभियान इन हाथियों को बचाने और इस प्रथा को 2030 तक खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। दुनिया भर में हर साल 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हाथियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इन शानदार जानवरों की रक्षा के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।

भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलीफेंट एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य हाथियों के प्राकृतिक आवासों में उनके लंबे समय तक अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। इसके बावजूद जंगलों के कटने और हाथियों के प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण की रोकथाम के बगैर यह विशाल और महत्वपूर्ण जानवर अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

समाज में परिवर्तन की वाहक बने बालिकाएं

मनोज शर्मा

आज हर क्षेत्र में बालिकाओं के आगे बढ़ने के बावजूद भी वह अनेको कुरीतियों की शिकार हैं। ये कुरीतियों उनके आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करती है। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय पालन दिवस है। 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार बालिका दिवस मनाया गया था। तब से हर वर्ष 11 अक्टूबर को पूरी दुनियां में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दुनिया भर में लड़कियों द्वारा उनके लिंग के आधार पर सामना की जाने वाली लैंगिक असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस असमानता में शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और भेदभाव से सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और जबरन बाल विवाह जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम है मैं लड़की हूं, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूं। संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियां। यह थीम संकट की परिस्थितियों में लड़कियों की दृढ़ता, नेतृत्व और सशक्त भूमिका पर केंद्रित है। यह थीम उन चुनौतियों पर प्रकाश डालती है जिनका सामना बालिकाएं करती हैं। जैसे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और असमानताएं। यह थीम बालिकाओं को केवल संकट के शिकार के रूप में नहीं बल्कि परिवर्तन के वाहक के रूप में पहचानने पर जोर देती है। यह थीम शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में निवेश का आ'ान करती है ताकि वे बेहतर और समावेशी दुनिया का निर्माण कर सकें। आज हर क्षेत्र में बालिकाओं के आगे बढने के बावजूद भी वह अनेको कुरीतियों की शिकार हैं। ये कुरीतियों उनके आगे बढने में बाधाएं उत्पन्न करती है। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। देश में आज भी प्रतिवर्ष लाखों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। आज भी समाज के अनेक घरों में बेटा, बेटी में भेद किया जाता है। बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। समाज में आज भी बेटियो को बोझ समझा जाता है।

भारत में हर साल तीन से सात लाख कन्या भ्रूण नष्ट कर दिये जाते हैं। इसलिए यहां महिलाओं से पुरुषो की संख्यो 5 करोड़ ज्यादा है। समाज में निरंतर परिवर्तन और कार्य बल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बावजूद रूढिवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा और बेटी हुई तो वह अपने घर चली जायेगी। बेटा अगर मुखाग्नि नहीं देगा तो कर्मकांड पूरा नहीं होगा।

पिछले कुछ वर्षों में देश में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी होना शुभ संकेत हैं। संसद में एक सवाल का जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में 12 अंकों के सुधार के

रूप में परिलक्षित होता है। जो कि 2014 में 918 था। जबकि 2023-24 में 12 अंक बढ़कर 930 हो गया। हमारे देश में यह एक बड़ी विडंबना है कि हम बालिका का पूजन तो करते हैं। लेकिन जब हमारे खुद के घर बालिका जन्म लेती है तो हम दुखी हो जाते हैं। देश में सभी जगह ऐसा देखा जा सकता है। देश के कई प्रदेशों में तो बालिकाओं के जन्म को अभिशाप तक माना जाता है। लेकिन बालिकाओं को अभिशाप मानने वाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि वह उस देश के नागरिक हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी विरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।

हमारे यहां आज भी बेटी पैदा होते ही उसकी परवरिश से ज्यादा उसकी शादी की चिन्ता होने लगती है। आज महंगी होती शादियों के कारण बेटी का बाप हर समय इस बात को लेकर चिंतित नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी। समाज में व्याप्त इसी सोच के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पायी है। कोख में कन्याओ को मार देने के कारण समाज में आज लड़कियों की काफी कमी होने से लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। अगर समाज में बेटियों को उचित शिक्षा और सम्मान मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नही रहेगी। इसलिए यदि यह कहा जाय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नही हम सबकी एक जिम्मेदारी है तो इसमें कुछ गलत नही है। यदि हम सभी एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते है तो हम सबका यही फर्ज बनता है हम बेटियों को भी भयमुक्त वातावरण में पढ़ाये। उन्हें इतना सशक्त बनाये की खुद गर्व से कह सके की देखो वह हमारी बेटी है जो इतना बड़ा काम कर रही है।

आज लड़किया लड़को से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। कठिन से कठिन कार्य लड़किया सफलतापूर्वक कर रही हैं। देश में हर क्षेत्र में महिला शक्ति को पूरी हिम्मत से काम करते देखा जा सकता है। लड़कियों ने अपने काम और समर्पण के दम पर कई क्षेत्रों और क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। वे अधिक प्रतिभाशाली, आज्ञाकारी, मेहनती और परिवार और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। लड़कियां अपने परिवार और माता-पिता के प्रति अधिक देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली होती हैं और वे हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देती हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का अहम योगदान है। वे श्रम शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाती हैं और व्यवसायों की वृद्धि और विकास में योगदान देती हैं। एक तरफ जहां बेटी को जन्मते ही मरने के लिये लावारिश छोड़ दिया जाता है। वहीं झुंझुनू जिले की मोहना सिंह जैसी बालिकायें भी है जो आज देश में फाईटर प्लेन उड़ा कर पूरे देश में जिले का मान बढ़ा रही हैं।

समाज में सभी को मिलकर लडका-लडकी में भेद नहीं करने व समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। देश में बालिकाओं के साथ हर दिन बलात्कारे, प्रताडना की घटनायें अखबारो की सुर्खिया बनती हैं। बालिकायें कही भी अपने को सुरक्षित नहीं समझती हैं। चाहे घर हो या स्कूल अथवा कार्य स्थल। हर जगह वहशी भेडिये उन पर नजरे गड़ायें रहते हैं। उन्हे जब भी मौका मिलता है नोंच डालते हैं। ऐसे माहौल में देश की बालिकायें कैसे आगे बढ़ पायेगीं। समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनोने कार्य को रोकने का माहौल बनाना होगा। ऐसा करने वाले लोगों को समझा कर उनकी सोच में बदलाव लाना होगा। लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा कि ना तो गर्भ में कन्या की हत्या करेगें ना ही किसी को करने देगें। तभी देश में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग पाना संभव हो पायेगा। सरकार व समाज को मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिये जिसमें बालिकायें खुद को महफूज समझ सकें। समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बालिकाओं के महत्व को स्वीकार करना और बढ़ावा देना आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि एक लड़की समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वह एक मां, एक बेटी, एक पत्नी इस तरह कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। उसे घर की शांति बनाए रखने वाली स्तंभ माना जाता है और फिर भी उसका अपमान किया जाता है। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती है फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही है। हमारे समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज अपनी बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें कितना महत्व देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक दायित्व है बल्कि सामाजिक विकास के लिए एक जरूरी आवश्यकता भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों को आगे बढ़ने, सीखने के समान अवसर मिले। तभी हम एक संतुलित, न्यायसंगत और समृद्ध समाज बना सकेगें।

दीपावली- सनातन धर्म-संस्कृति व परंपराओं का गौरवशाली पर्व

दीपावली का पर्व हर वर्ष शरद ऋतू की शुरूआत में आता है। यह पावन त्योहार भारतीय संस्कृति का प्रमुख पर्व है और इसको प्रतिवर्ष पवित्र कार्तिक मास की अमावस्या को बहुत ही जोशोखरोश के साथ देश व विदेशों तक में मनाया जाता है।

रवि जैन

विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म, संस्कृति की विविध प्रकार की परंपराओं के अनुसार हम सभी सनातनियों के जीवन में त्योहारों का विशेष स्थान है।

हम सनातनियों के यहां पर त्योहारों की एक पूरी लंबी श्रृंखला मनायी जाती है, हर माह कोई ना कोई त्योहार हम सबकी झोलियों को खुशियों से भरने का काम करता है, इन त्योहारों के दम पर अगर हम भारत को त्योहारों की अद्भुत संस्कृति के महाकुंभ से संपन्न देश कहें तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्यारे देश में वर्ष भर तिथि व वार के अनुसार आयेदिन कोई न कोई पर्व या उत्सव लगातार चलते ही रहते है।

हालांकि कुछ उत्सव केवल देश के किसी क्षेत्र विशेष में मनाए जाते हैं तो कुछ उत्सव सम्पूर्ण देश में अलग-अलग नाम व तौर-तरीकों से मनाये जाते हैं। वैसे भी विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म की गौरवशाली परंपराओं के अनुसार शायद ही कोई माह या ऋतु ऐसी होगी, जिसमें हम लोग कोई त्योहार ना मनाये, यही हमारी संस्कृति का गौरवशाली इतिहास व आज रहा है। वैसे भी देखा जाए तो त्योहार या उत्सव के महत्वपूर्ण अवसर हमारे जीवन में एक नया उत्साह संचार करने के

व उपहार आदि देते हैं। इस त्योहार में एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि वह हम लोगों में आपसी प्यार, सौहार्द के साथ परिवार की तरह रहने के लिए प्रेरित करती है तथा यह त्योहार हम सभी के जीवन में एक नई सकारात्मक उर्जा का संचार कर देता है।

इस त्योहार को हम लोग दीपावली या आम-बोलचाल की भाषा में दीवाली के नाम से भी पुकारते हैं। दीपावली हम सभी के जीवन में खुशियों के नये रंग भरने वाला बहुत ही शानदार त्योहार है। जो देश व समाज में हर तरफ प्रकाश की नवज्योति फैलाते हुए लोगों के जीवन को हर्षोल्लास, आनंद से परिपूर्ण कर देता है।

सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति के जीवन में दीपावली का एक बहुत बड़ा महत्व होता हैं। शास्त्रों के अनुसार यह त्योहार व्यक्ति के जीवन को 'अंधेरे से ज्योति' अर्थात प्रकाश की ओर लेकर जाता है। इस त्योहार पर प्रत्येक सनातनी मनुष्य अपने जीवन के गम के अंधेरों को भुलाकर, जीवन को एक नये उजाले की ओर ले जाने का ठोस प्रयास करता है। मेरा मानना हैं कि आज के भागदौड़ भरे आपा-धापी वाले इस व्यवसायिक दौर में सही में दीपावली वह है जब व्यक्ति अपने मन के अंधेरों को प्रण लेकर स्थाई रूप से खत्म करके, जीवन में प्रकाशमयी सकारात्मक उर्जा के साथ लोगों के साथ मिलजुलकर प्यार मोहब्बत से जीवन की अद्भुत लीलाओं भरपूर आनंद ले। तब ही जीवन में प्रकाश व खुशियों की दीपमाला को झिलमिलाने वाले पावन पर्व दीपावली के त्योहार का असली उद्देश्य पूर्ण होता है।

मैं दीपावली के पावन पर्व की इस श्रृंखला पर सभी देशवासियों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी देशवासियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।

90 दिनों में पाएं मनचाहा फिगर ! वेट लॉस के 5 टॉप सीक्रेट्स

90 दिनों में वजन घटाकर मनचाहा फिगर पाने हेतु फिटनेस कोच ने 5 प्रभावी रणनीतियाँ बताई हैं, जिनमें खाली पेट कार्डियो और हफ्ते में 4-5 दिन वेट ट्रेनिंग शामिल है। संतुलित प्रोटीन सेवन के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग और ठंडे पानी से नहाना मेटाबॉलिज्म को गति देकर फैट बर्न करने में सहायक है।

फिट दिखने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। लोग फिट रहने के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं। एक बार वजन बढ़ जाए तो इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। अगर सही समय पर वजन को कंट्रोल किया जाए, तो आपका वजन कम होने लगता है। यदि आप ज्यादा ही मोटे हो गए हैं, तो 3 महीने के अंदर फिटनेस कोच ने बताएं वजन कम करने टिप्स। तीन महीने के अंदर आप हो जाएंगे पतले। आइए आपको बताते हैं आसान फिटनेस प्लान।

सुबह खाली पेट करें कार्डियो

फिटनेस कोच ने बताया है कि खाली पेट एक्सरसाइज या कार्डियो करना फैट बर्न करने का सबसे आसान तरीका है। रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक वॉक करें या हल्की जॉगिंग जरुर करें। इससे शरीर का जल्दी फैट बर्न करता है। शरीर में जमा हुआ फैट एनर्जी को रुप में प्रयोग होता है। वजन भी कम होने लगता है।

हफ्ते में 5 दिन करें वेट ट्रेनिंग

वजन कम करने के लिए सिर्फ वॉक या रनिंग से कुछ नहीं होने वाला है। यदि आपको फिट दिखने के साथ ही स्ट्रॉन्ग बनना है, तो वेट ट्रेनिंग भी जरुरी है। आप कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार वेट उठाने वाले एक्सरसाइज करें। इसके लिए आप स्क्वैट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस। एक्सरसाइज तेजी से ज्यादा कैलोरी बर्न करती हैं और इसके साथ ही लीन मसल्स बनाती है।

प्रोटीन पर ध्यान दें

यदि आपको वजन कम करना है, तो आप प्रोटीन की सही मात्रा जरुर लें। रोज अपने वजन के हिसाब से एक ग्राम प्रोटीन जरुर लें। जैसा कि-किसी का वजन 60 किलो है, तो उसे 130 ग्राम प्रोटीन लेना जरुरी है। प्रोटीन लेने से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती और मसल्स को टूटने से भी बचाता है। आप अपनी डाइट में अंडे, दाल, पनीर, दही, चिकन या सोया प्रोटीन जैसे ऑप्शंस सबसे बेहतर है।

ठंडे पानी से नहाएं

ठंडे पानी से नहाने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होगा। ठंडा पानी शरीर को एक्टिव रखता है और फैट बर्न करने में मदद करता है। शुरूआत में आपको काफी परेशान होगी लेकिन बाद में आपको इसकी आदत हो जाएगी।

इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाएं

वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग भी काफी जरुरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब आप दिन का खाना कम कर दें। ऐसा करने से वजन जरुर कम होता है। चाहे तो आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर सकती हैं और खाने का समय 6 से 8 घंटे का कर सकती हैं। ऐसा करने से शरीर की कैलोरी अपने आप कम हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र भी बेहतर रहेगा।

घर बैठे पाएं सॉफ्ट, सिल्की और घने बाल!

तुलसी का ये घरेलू नुस्खा देगा हैरान करने वाला रिजल्ट

रुखे और बेजान बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए तुलसी का पानी एक प्रभावी घरेलू नुस्खा है। यह बालों को सॉफ्ट, सिल्की, लंबा और घना बनाने के साथ-साथ डैंड्रफ व बालों के झड़ने को भी कम करता है। तुलसी के पानी को शैंपू के साथ मिलाकर या हेयर मास्क में इस्तेमाल कर बालों की समग्र देखभाल की जा सकती है।

चेहरे की खूबसूरती की देखभाल करने के साथ ही बालों का ध्यान रखना काफी जरुरी होता है। बदलते मौसम में बाल रुखे और बेजना होने लगते हैं। जिस वजह अंदरुनी सुंदरता में कम होने लगती है। यदि आप भी बालों की खूबसूरती को बढ़ाना चाहती हैं और उन्हें सॉफ्ट, सिल्की, लंबा और घना बनाने का कोशिश में लगी हो, तो आप घर में रहकर एक खास घरेलू उपाय कर सकती है। आप तुलसी के पानी को अपने बालों में अप्लाई कर सकती है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बालों के झड़ने और डैंड्रफ कम करने में मदद करता है। आइए आपको बताते हैं तुलसी के पानी का बालों के लिए किस तरह से यूज करें।

कैसे करें तुलसी पानी का इस्तेमाल

तुलसी का पानी इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप तुलसी के 15 से 20 पत्ते लें और उन्हें

गर्म पानी में अच्छे से गला लें, इसके बाद पानी को ठंडा होने दें। अब आप साधा पानी और तुलसी के पानी दोनों को मिक्स कर थोड़ा शैंपू मिलाकर अपने बालों को धो सकती हैं। अगर आप माइल्ड शैंपू यूज करें तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा।

तुलसी के साथ नीम के पत्तों का पानी

आप चाहे तो तुलसी के पानी के साथ नीम के पत्तों का पानी मिलाकर अपने बालों पर कम से कम 20 से 25 मिनट तक लगा सकते हैं। इसके बाद आप शैंपू से अपने बालों को धो लें। यह घरेलू नुस्खा का इस्तेमाल करने से आपको काफी फायदा मिलेगा। आप चाहे तो बालों के लिए हेयर मास्क बनाते हुए तुलसी का पानी यूज कर सकती हैं। हेयर मास्क में तुलसी के पानी एड ऑन करने से कई लाभ मिलते हैं। यह डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है।

इन बातों को रखें ध्यान

यदि आप पहली बार तुलसी का पानी बालों के लिए प्रयोग कर रहे है, तो सबसे पहले पैच टेस्ट जरुर करें। इसके बाद ही इस्तेमाल करें। पैच टेस्ट के दौरान आपको कोई परेशानी हो, तो डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह जरुर लें और इसका यूज करना बंद कर दें।

पालमपुर के नजदीक ये एडवेंचर हिल स्टेशन हैं पर्यटकों के छिपे हुए खजाने

पालमपुर शहर को काफी कम लोग हिल स्टेशन मानते हैं। इसलिए लोग पालमपुर के आसपास में स्थित खूबसूरत और शानदार हिल स्टेशन की तलाश में रहते हैं। हम आपको पालमपुर के आसपास में स्थित कुछ शानदार हिल स्टेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

अरुण मिश्रा

दिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पालमपुर एक खबूसूरत पहाड़ी शहर है।

पालमपुर अपनी खूबसूरती के अलावा हरे-भरे चाय के बागानों और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के लिए भी जाना जाता है। पालमपुर अपने सुंदर और अलौकिक प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इस शहर को काफी कम लोग हिल स्टेशन मानते हैं। इसलिए लोग पालमपुर के आसपास में स्थित खूबसूरत और शानदार हिल स्टेशन की तलाश में रहते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको पालमपुर के आसपास में स्थित कुछ शानदार हिल स्टेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर आप अपने परिवार, पार्टनर और दोस्तों के साथ सुकून के पल बिताने के लिए पहुंच सकते हैं।

पालमपुर के आसपास जब भी किसी खूबसूरत हिल स्टेशन घूमने की बात होती है, तो सबसे पहले लोग धर्मशाला का रुख करते हैं। आप अगर धर्मशाला घूमने जा रहे हैं, तो यहां से करीब 5 किमी दूर स्थित मैक्लोडगंज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गर्मियों में मैक्लोडगंज और धर्मशाला घूमने के लिए देश के हर कोने से पर्यटक घूमने पहुंचते हैं। जून-जुलाई के महीने में भी यहां पर ठंडी-ठंडी हवाएं चलती हैं।

मुख्य आकर्षण

- भागसू वाटरफॉल
- धर्मकोट

- धर्मशाला टी गार्डन
- बीर बिलिंग

समुद्र तल से करीब 2 हजार मीटर की ऊंचाई पर बीर बिलिंग स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जगह अधिक पैराग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है। पैराग्लाइडिंग के लिए बीर बिलिंग दुनिया भर के पर्यटक पहुंचते हैं। यहां पर आप ट्रेकिंग से लेकर कैंपिंग और हाइकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। गर्मियों में भी यहां का मौसम सुहावना होता है।

मुख्य आकर्षण

- बीर सनसेट पॉइंट
- चोकलिंग मठ
- गुनेहर वॉटरफॉल

बरोट हिल स्टेशन

हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में स्थित बरोट हिल स्टेशन एक छिपा हुआ खजाना माना जाता है। बरोट अपने घने जंगह, बादलों से ढके ऊंचे-ऊंचे पहाड़, झील-झरनों और देवदार के बड़े-बड़े पेड़ों के लिए जाना जाता है। यहां की ठंडी हवाओं में आप अपने परिवार, पार्टनर और दोस्तों के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग माना जाता है।

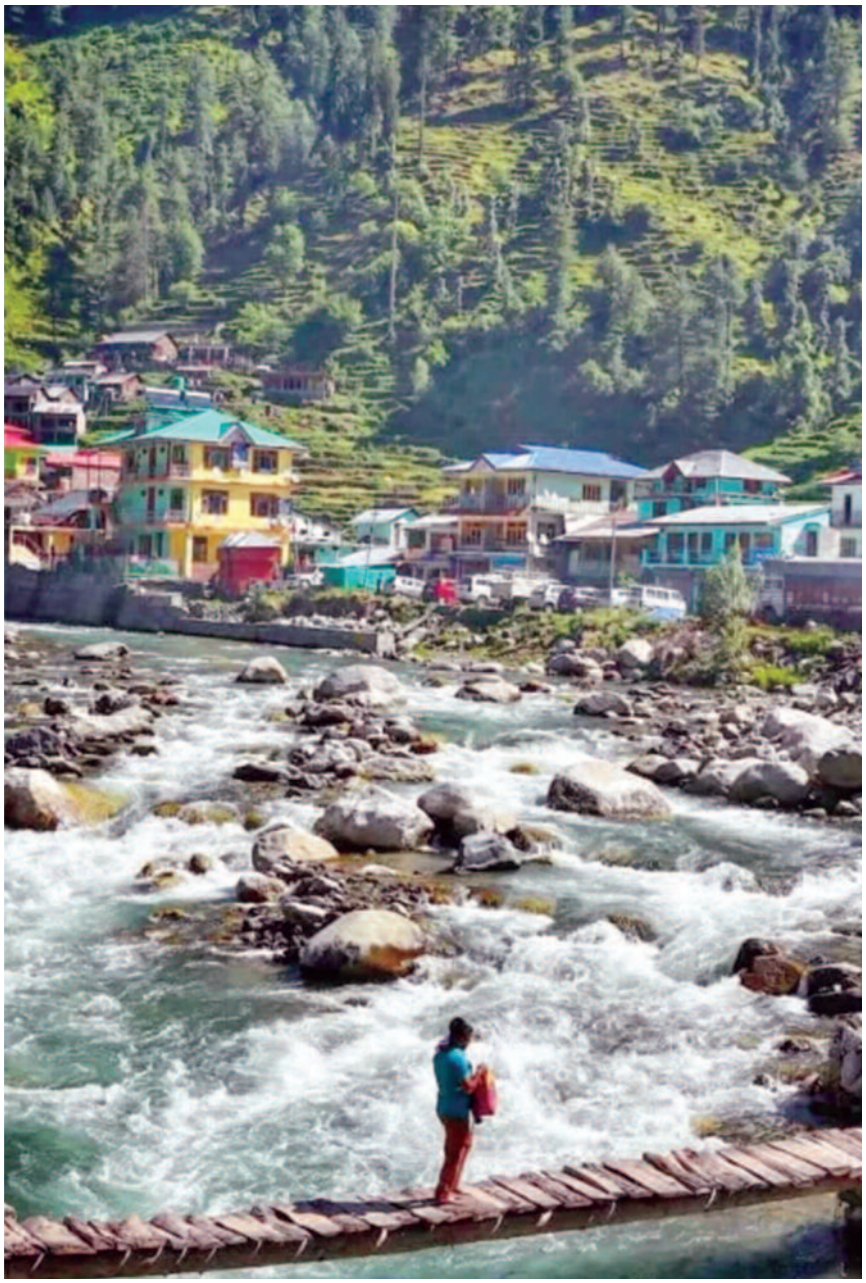

मुख्य आकर्षण

- बरोट मंदिर
- बाडा ग्रान ट्रेक
- लापस वॉटरफॉल

कुल्लू

कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत जिला और हिल स्टेशन है। यह मंडी-मनाली राजमार्ग पर पड़ता है, जोकि अपने शांत वातावरण और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां पर आपको ऊंचे-ऊंचे पहाड़, झील-झरने और घास के मैदान देखने को मिलेंगे। जून की छुट्टियों में कई लोग कुल्लू घूमने के लिए पहुंचते हैं।

मुख्य आकर्षण

- फ्रेंडशिप पीक
- नग्गर कैसल
- भृगु झील

समाज में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता और समावेशी सोच को बढ़ावा देने का प्रयास

डॉ. बी जमा

विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के अवसर पर भागीरथ सेवा संस्थान, फर्स्टवन रिहैब फाउंडेशन एवं राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फरेंस संपन्न हुई। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज को सेरेब्रल पाल्सी जैसी विशेष दिव्यांगता के प्रति जागरूक करना और इससे प्रभावित बच्चों एवं उनके अभिभावकों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। कार्यक्रम में भारत सरकार में राज्यमंत्री बीएल वर्मा (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) ने मुख्य अतिथि के रूप शिरकत की। उत्तराखंड सरकार में राज्यमंत्री वीरेंद्र दत्त सेमवाल (हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद) ने विशिष्ट अथिति के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में देशभर से ख्यातिप्राप्त रिहैबिलिटेशन विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आयुर्वेद विशेषज्ञ, पैडियाट्रिशियन तथा विशेष शिक्षा विशेषज्ञ ने भाग लिया लिया।

इन सभी विशेषज्ञ ने विभिन्न प्रेजेंटेशन और तकनीकी सत्रों के माध्यम से सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ी आधुनिक उपचार पद्धतियों, पुनर्वास तकनीकों और नए शोधों की जानकारी साझा की साथ ही बेहतर कार्य कर रहे डाक्टर त्रिभुवन सिंह, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ.धीरज सिंह, डॉ. नरेंद्र पांडेय, डॉ. अभिषेक पांडेय, डॉ. विजय प्रकाश, डॉ. राहुल शुक्ला समेत कई डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ फिज़ियोथेरेपिस्ट एवं होली फैमिली अस्पताल में 40 से अधिक वर्षों तक सेवाएँ देने वाली डॉ. सुनीता सूद मोजूद रही। फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन के निदेशक डॉ महिपाल सिंह ने बताया कि सम्मेलन में सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों, उनके अभिभावकों और रिहैब प्रोफेशनल्स के लिए विशेष इंटरएक्टिव सत्र रखे गए हैं, ताकि उन्हें व्यवहारिक समाधान और प्रेरणा मिल सके। कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स द्वारा विषय पर व्याख्यान के साथ साथ भागीरथ स्पेशल स्कूल और फर्स्टवन रिहैब फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गयी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए नेशनल वोची टूनार्मेंट में गोल्ड सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर आये भागीरथ स्पेशल स्कूल के बच्चों प्राची, खुशी, आंचल और इंस्ट्रक्टर अंकित एवं कोच सुमन राजपूत को मंत्री बीएल वर्मा द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए यह प्रोफेशनल को दिव्यांगता के प्रति उनकी विशेष सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिव्यांग जन के लिए अपने-अपने मंत्रालय के अधीन जो भी सहयोग हो सकेगा करेंगे। इस दौरान फर्स्टवन रिहैब फाउंडेशन के निदेशक डॉ. महिपाल सिंह तथा डाक्टर दीक्षा सिंह एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुष्मिता भाटी आदि मौजूद रहे।

वैज्ञानिकों का 'महाठंड' अलर्ट, सर्दी-जुकाम से बचने के लिए रखें ये 4 रामबाण चीजें

डॉ. मुकुल शर्मा

अधिक सर्दी और प्रदूषण होने के कारण लोगों को इंफेक्शन, फ्लू, बुखार, खांसी, ठंड लगना और अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन आदि हो सकता है। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत ज्यादा बिगड़ सकती है। क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है।

इस बार की सर्दी को लेकर अभी से वैज्ञानिक चेतावनी जारी करने में लगे हैं। ला नीना इफेक्ट की वजह से इस बार के मानसून में भारी बारिश देखने को मिली है। एक्सपर्ट के अनुसार, अगर यह इफेक्ट जारी रहता है, तो उत्तर भारत में इस बार भयंकर ठंड हो सकती है। इसके अलावा इंफेक्शन और पॉल्यूशन आदि का भी खतरा लोगों पर मंडरा सकता है। अधिक सर्दी और प्रदूषण होने के कारण लोगों को इंफेक्शन, फ्लू, बुखार, खांसी, ठंड लगना और अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन आदि हो सकता है। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत ज्यादा बिगड़ सकती है। क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है। ऐसे में आप भी पंसारी से 4 चीजें लाकर घर में रखें और सर्दियां पड़ने पर इनका इस्तेमाल करें।

पीपली पाउडर

एक्सपर्ट के अनुसार, सर्दियों में पीपली का सेवन जरूर करना चाबिए। रोजाना इसका पाउडर कुछ चुटकी लेकर शहद के साथ खाना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है, जोकि आपको सर्दी-खांसी से बचाने का काम करती है। यह पेट में अग्नि बढ़ाती है, जोकि ठंड में आमतौर पर काफी कम होती है।

मुलेठी

ठंड लगने की वजह से गले में सूजन, खराबी और दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके लिए मुलेठी या फिर इसके पाउडर का सेवन करना चाहिए। इससे न सिर्फ गले में आराम मिलेगा, बल्कि खांसी और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सही रहेगा।

सोंठ पाउडर

अदरक को सुखाकर बनाए जाने वाले पाउडर को सोंठ कहा जाता है। सोंठ अदरक के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। इस कारण सर्दियों में सोंठ का सेवन किया जाता है। फ्लू, बुखार और कमजोर पाचन से यह बचाता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं।

गुड़ का सेवन

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ठंड के मौसम में गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस दौरान प्रदूषण बढ़ने से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। रात में थोड़ा सा गुड़ खाने से सांस नली और मुंह में अटके प्रदूषण कण से राहत मिलती है। हालांकि डायबिटीज के रोगियों को गुड़ का सेवन डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए।

इन मसालों का इस्तेमाल करें

बता दें कि ऊपर बताई गई चीजों के अलावा खाने में मसालों का इस्तेमाल जरूर करें। अदरक, हल्दी, दालचीनी और कालीमिर्च का सेवन आपके रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपको बीमार पड़ने से बचाता है। रोजाना नीम और तुलसी की पत्तियां चबाकर जरूर खाना चाहिए।

असरानी को भावभीनी श्रद्धांजलि

अलविदा 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर'

गोवर्धन असरानी, जिन्हें हम सब प्यार से असरानी कहते थे, भारतीय सिनेमा के सबसे प्रिय हास्य अभिनेता थे। उनके अभिनय में विनम्रता, सादगी और अद्भुत हास्य का संगम था। शोले के 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' से लेकर गोलमाल, बावर्ची और चुपके चुपके तक, उन्होंने हर किरदार में जीवन की सच्चाई दिखायी। युवा हों या वृद्ध, सभी उनकी हँसी और संवादों के दीवाने थे। सरल जीवन, निष्ठा और कला के प्रति समर्पण उनके व्यक्तित्व का मूल था। भारतीय सिनेमा उनका योगदान हमेशा याद रखेगा।

भारतीय चलचित्र जगत ने एक और प्रकाशपुंज खो दिया। हास्य अभिनय के महारथी, सरल स्वभाव के धनी और हर पीढ़ी को हँसाने वाले कलाकार गोवर्धन असरानी, जिन्हें संसार प्यार से केवल असरानी कहता था, अब इस नश्वर संसार से विदा ले चुके हैं। उनके निधन के साथ भारतीय सिनेमा का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है। परन्तु उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनका सहज अभिनय सदैव जीवित रहेगा।

असरानी का जीवन केवल अभिनय की कहानी नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें परिश्रम, लगन, अनुशासन और कला के प्रति गहरा समर्पण समाहित था। वे उन विरल कलाकारों में से एक थे जिन्होंने दर्शकों को यह सिखाया कि हँसी केवल ठहाका नहीं होती, बल्कि जीवन की जटिलताओं को हल्का करने का साधन भी होती है। उनके अभिनय में हास्य की गंभीरता और संवेदना दोनों एक साथ दिखाई देती थीं।

असरानी का जन्म सन् 1941 में जयपुर नगर में एक सिंधी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अभिनय की ओर आकर्षित थे। उनके परिवार को यह स्वप्न नहीं था कि एक दिन उनका बेटा भारतीय चलचित्रों में एक प्रसिद्ध नाम बनेगा, परंतु असरानी के भीतर कला का दीप बचपन से ही प्रज्वलित था। विद्यालय के नाटकों में उन्होंने भाग लिया और वहीं से अभिनय का बीज अंकुरित हुआ। युवावस्था में उन्होंने पुणे स्थित भारतीय चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उस संस्थान ने उन्हें न केवल अभिनय का अभ्यास सिखाया बल्कि कला के गहरे दर्शन से भी परिचित कराया। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने मुंबई नगर का रुख किया – वही नगर जिसने असंख्य स्वप्नदर्शियों को गले लगाया और असंख्य को असफलताओं की धूल में मिला दिया। परंतु असरानी उन लोगों में थे जो असफलताओं से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते हैं।

असरानी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हास्य को हल्केपन से नहीं, बल्कि गंभीरता से निभाते थे। उनका कहना था कि 'लोगों को हँसाना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि उसमें सच्चाई छिपी होती है।' उन्होंने दर्शकों को यह महसूस कराया कि हँसी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। उनका हास्य कभी अशिष्ट नहीं हुआ। उनके संवादों में एक मयार्दा थी, एक विनम्रता थी। वे दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान लाते थे, परंतु किसी की गरिमा को ठेस

नहीं पहुँचाते थे। यही कारण है कि वे पीढ़ियों तक प्रिय बने रहे।

सन् 1975 में जब शोले प्रदर्शित हुई, तो उसमें अनेक पात्रों ने इतिहास रचा-जय, वीरू, गब्बर सिंह, ठाकुर और इसी श्रेणी में था वह जेलर, जो हर बार अपनी अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में दर्शकों को हँसा देता था। 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं...' यह संवाद आज भी भारतीय जनमानस में जीवित है। असरानी ने इस किरदार को केवल निभाया नहीं, बल्कि उसमें प्राण फूँक दिए। उनकी आँखों की चपलता, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा-सब कुछ ऐसा था कि दर्शक हर बार उस दृश्य के आने पर मुस्कुरा उठते थे। इस एक भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया, परंतु उन्होंने स्वयं को कभी इस एक छवि तक सीमित नहीं होने दिया।

असरानी का अभिनय केवल हास्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने गंभीर भूमिकाएँ भी निभाईं। बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, गोलमाल, नमक हराम, कुली नंबर एक, दिल है कि मानता नहीं, हेरा फेरी जैसी अनेक चलचित्रों में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। वे ऐसे कलाकार थे जो किसी भी परिस्थिति में ढल जाते थे। निर्देशक उनके चेहरे को देखकर समझ जाते थे कि इस व्यक्ति में असीम संभावनाएँ छिपी हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो दर्शकों के कानों में सीधे उतर जाती थी। उन्होंने मंच, दूरदर्शन और चलचित्र-तीनों माध्यमों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

असरानी के लिए अभिनय केवल जीविका नहीं, बल्कि एक साधना था। वे कहा करते थे, 'कलाकार वह दर्पण है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। अगर हँसी के जरिए मैं समाज की थकान दूर कर सकता हूँ, तो वही मेरा पुरस्कार है।' उनका यह दृष्टिकोण उन्हें सामान्य हास्य कलाकारों से ऊपर उठा देता था। वे हँसी के साथ विचार भी देते थे। उनकी प्रस्तुति कभी फूहड़ नहीं होती थी; उसमें मानवता का तत्व होता था।

असरानी जी का स्वभाव अत्यंत विनम्र था। उन्होंने अपने सह-अभिनेताओं के साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार किया। चाहे राजेश खन्ना हों, अमिताभ बच्चन हों या धर्मेन्द्र-सभी ने उनके साथ कार्य करना आनंददायक बताया। वे सेट पर हल्के-फुल्के वातावरण का निर्माण करते थे। कठिन दृश्यों में भी वे वातावरण को सहज बना देते थे। उनके साथी कलाकार कहते हैं कि असरानी जी का हँसी-मजाक केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता था, बल्कि वह तनाव को दूर करने का साधन होता था।

बहुत से लोग नहीं जानते कि असरानी ने केवल अभिनय ही नहीं किया, बल्कि निर्देशन और शिक्षण के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उन्होंने नवोदित कलाकारों को अभिनय की बारीकियाँ सिखाईं। वे अक्सर कहा करते थे, 'हास्य अभिनय केवल चेहरा बिगाड़ने या अजीब चाल चलने का नाम नहीं है; यह दिल की सच्चाई से उपजता है।' उन्होंने युवा कलाकारों को सिखाया कि कैमरे के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता। दर्शक हर झूठ को पकड़ लेते हैं। इसलिए अभिनय का आधार ईमानदारी होना चाहिए।

असरानी जी का सबसे बड़ा पुरस्कार यही था कि वे हर उम्र के दर्शकों के प्रिय थे। बुजुर्ग उन्हें पुराने दौर की यादों से जोड़ते थे, युवा उन्हें हल्के-फुल्के हास्य के प्रतीक मानते थे, और बच्चे उन्हें अपने मजेदार अंकल के रूप में देखते थे। उनकी आवाज सुनते ही चेहरा मुस्कुरा उठता था। वे हर वर्ग के लिए आत्मीय थे।

अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी असरानी सक्रिय रहे। उन्होंने कई धारावाहिकों और नाटकों में भाग लिया। वे कहते थे कि 'जब तक साँस है, अभिनय चलता रहेगा।' वे कभी भी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे। उन्होंने सरल जीवन जिया, और यही सरलता उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उनका निधन 84 वर्ष की आयु में हुआ, परंतु वे अंतिम दिनों तक सक्रिय रहे। वे न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि भारतीय चलचित्र जगत के लिए भी प्रेरणा बन गए।

असरानी का योगदान केवल अभिनय तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हँसी भी एक गंभीर कला है। उन्होंने दर्शकों को यह सिखाया कि हर परिस्थिति में मुस्कराना संभव है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। हर वह कलाकार जो हास्य के क्षेत्र में कार्य करेगा, कहीं न कहीं असरानी से प्रेरणा लेगा। उनके संवाद, उनकी शैली, उनकी आत्मीयता—सब कुछ भारतीय सिनेमा की स्मृतियों में अमिट रहेंगे।

असरानी जी का जीवन यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को अगर मन से किया जाए, तो वह कला बन जाता है। उन्होंने संघर्ष किया, असफलताएँ देखीं, परंतु कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। वे यह भी मानते थे कि कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में आशा और सहानुभूति जगाना है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि विनम्रता, ईमानदारी और परिश्रम-यही किसी कलाकार की सच्ची पहचान हैं।

आज जब असरानी जी हमारे बीच नहीं हैं, तो ऐसा लगता है मानो भारतीय सिनेमा का एक प्रिय स्वर मौन हो गया हो। परंतु उनकी हँसी, उनका चेहरा और उनका अभिनय हमारे भीतर सदा जीवित रहेगा। वे जहाँ भी होंगे, शायद वहाँ भी अपनी विशिष्ट शैली में कह रहे होंगे - 'आर्डर! आर्डर! अदालत की कार्यवाही स्थगित की जाती है!' उनकी आत्मा को शांति मिले। भारतवर्ष सदैव उनका आभारी रहेगा।

असरानी – एक नाम, एक मुस्कान, एक युग। सिनेमा की हँसी अब कुछ कम हो गई है, पर असरानी की यादें सदैव गूंजती रहेंगी।

बदला हुआ भारत: क्रिकेट और आत्मसम्मान का नया अध्याय

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत का रुख और खेल के मैदान से परे राष्ट्रीय गौरव की झलक

एशिया कप 2025 का फाइनल केवल क्रिकेट का खेल नहीं था। भारत ने पाकिस्तान को हराने के साथ ही ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पुरस्कार देने वाला पाकिस्तान का प्रतिनिधि था। इससे प्रस्तुति समारोह घंटों तक लंबित रहा। इस कदम ने केवल खेल में जीत नहीं दिखाई, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान और राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट किया। समर्थक इसे 'नए भारत' की शक्ति और साहस मानते हैं, जबकि आलोचक खेल भावना पर चोट मानते हैं। यह घटना भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक यादगार मोड़ है, जो खेल, राजनीति और राष्ट्रीय गौरव को जोड़ती है।

एशिया कप 2025 का अंतिम मुकाबला केवल क्रिकेट का रोमांचक खेल नहीं था। यह खेल से कहीं अधिक एक कूटनीतिक और सांस्कृतिक संदेश बनकर उभरा। भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ. मैदान पर हराया बल्कि मैच के बाद की औपचारिकताओं में भी ऐसा रुख अपनाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई क्रिकेट परिषद के

महमूद रजा
बिजनौर

अध्यक्ष, जो पाकिस्तान से हैं, से ट्रॉफी स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पुरस्कार वितरण समारोह घंटों तक खिंचता रहा और अंततः अधूरा रह गया। यह घटना भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सवाल केवल इतना नहीं है कि ट्रॉफी किसने थामी, बल्कि यह कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया और इसके परिणाम क्या हैं।

क्रिकेट को अक्सर 'जेंटलमैन का खेल' कहा जाता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संदर्भ

में यह खेल कभी केवल खेल नहीं रहा। यह दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव, सांस्कृतिक टकराव और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन चुका है। जब भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया, तो यह स्पष्ट संदेश था कि मैदान की जीत से आगे बढ़कर भारत अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानता है। एक तरह से यह 'खेल और कूटनीति का उल्टा रूप' था। जहाँ खेल को आमतौर पर राजनीति को नरम करने का साधन माना जाता है, वहीं भारत ने खेल का मंच उपयोग करके राजनीतिक संदेश दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बार-बार यह दावा किया गया है कि भारत अब झुकता नहीं, बल्कि अपनी शर्तें तय करता है। इस संदर्भ में टीम इंडिया का रुख उसी मानसिकता का विस्तार माना जा रहा है। भारत के लिए ट्रॉफी लेना केवल एक औपचारिकता था, लेकिन जब देने वाला वही देश हो जिससे लगातार आतंकवाद, घुसपैठ और सीमा पर तनाव चलता रहा है, तो उस औपचारिकता का महत्व बदल जाता है। यह नया भारत केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति की भाषा में नहीं बोलता, बल्कि खेल के मंच पर भी राजनीतिक संदेश देने में पीछे नहीं है। इसके साथ ही घरेलू राजनीति में भी इस घटना का गहरा असर पड़ा। समर्थक वर्ग इसे मोदी युग का साहसिक कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे खेल भावना पर चोट मानता है। हालांकि जनता में इसे व्यापक रूप से आत्मगौरव की जीत के रूप में देखा गया।

हर साहसिक कदम के साथ आलोचना भी जुड़ती है। भारत के इस रुख को लेकर कई सवाल उठे। आलोचकों का कहना है कि क्रिकेट का मूल उद्देश्य देशों के बीच दोस्ती और सौहार्द बढ़ाना है। जब आप ट्रॉफी लेने से इनकार करते हैं, तो आप खेल की आत्मा पर चोट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस घटना पर मिला-जुला रुख अपनाया। कुछ ने इसे भारत की 'दबदबा दिखाने की नीति' कहा, तो कुछ ने इसे 'अहंकार' बताया। सवाल यह है कि क्या इससे भारत की 'नरम शक्ति' को नुकसान होगा। साथ ही यह भी बहस छिड़ी कि क्या खिलाड़ियों ने यह कदम अपनी इच्छा से उठाया या बोर्ड और सरकार के दबाव में? अगर खिलाड़ी राजनीतिक निर्णयों में केवल मोहरे बन जाएँ, तो उनकी स्वतंत्रता और खेल की पवित्रता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट में विवाद कोई नई बात नहीं है। 1987 में जब पाकिस्तान के

राष्ट्रपति जयपुर टेस्ट देखने आए थे, तब इसे 'क्रिकेट कूटनीति' कहा गया। 1999 में कारगिल युद्ध से पहले चेन्नई टेस्ट में पाकिस्तान की जीत और उसके बाद की राजनीतिक हलचल को भी आज तक याद किया जाता है। 2008 में मुंबई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला हमेशा के लिए रोक दी। 2023 में एशिया कप को लेकर स्थान विवाद खड़ा हुआ, जहाँ भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और अंततः प्रतियोगिता 'संयुक्त रूप' में आयोजित हुई। इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में देखें तो 2025 की घटना कोई अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि उसी लंबे सिलसिले का हिस्सा है जहाँ क्रिकेट हमेशा

राजनीति के साए में खेला गया।

इस घटना के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भले ही दुबई में है, लेकिन पाकिस्तान लंबे समय से इसमें प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी सहमति के बिना कोई ढांचा नहीं चल सकता। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद तटस्थता का दावा करती है, लेकिन अगर बड़ी टीमों में से एक यानी भारत इस तरह के कदम उठाकर राजनीतिक संदेश देती है, तो परिषद को मजबूरी में अपना रुख तय करना होगा। बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीमें इस खींचतान के बीच कहाँ खड़ी होंगी, यह भी देखने वाली बात है। भारत का दबाव इन्हें प्रभावित करेगा, लेकिन लंबे समय में यह क्षेत्रीय सहयोग को कमजोर कर सकता है।

भारत का यह रुख निश्चित रूप से 'नए भारत' का प्रतीक है। यह भारत का वह चेहरा है जो आत्मगौरव को सर्वोपरि मानता है और औपचारिकता या परंपरा को उसके आगे झुका देता है। लेकिन इसी के साथ यह भी सच है कि खेल की आत्मा को राजनीति से बहुत अधिक जोड़ना कभी-कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। क्या भारत ने सही किया? समर्थकों के लिए जवाब सीधा है- हाँ, क्योंकि यह आत्मसम्मान का सवाल था। आलोचकों के लिए जवाब है- नहीं, क्योंकि खेल का मंच राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए।

TCL

Global TOP 1 Mini LED TV Brand
by the shipment market share of Mini LED TVs in 2024

TCL GRAND DIWALI DHAMAKA

This Diwali, Buy a TCL 55 Inch or above
QD Mini LED TV & Win Exciting Prize!

55 Starts From ₹ 45,990* Less Cashback* (T&C*)

C6K *PREMIUM* QD-Mini LED TV

ROHIT SHARMA
BRAND AMBASSADOR, TCL INDIA

Weekly Treats
40 Weekly Winners will win E-Gift Vouchers for Festive Feasts

Scan to Enter

Festive Getaway
20 Winners will win Flight Ticket Vouchers for Holiday Journeys

Festive Bonus
10 winners will win an Exclusive Meet & Greet with Rohit Sharma*

Valid From Sep 20th - Oct 26th

TCL Premium Mini LED TV & QLED TV Range

C6KS — TCL *PREMIUM* QD-Mini LED TV

True Colors, True Details

185 cm (75) | 160.8 cm (65) | 136 cm (55)

55 Starts From ₹ 43,990* Less Cashback* (T&C*)

P7K — TCL *PREMIUM* QLED TV

Vivid and Vibrant

185 cm (75) | 160.8 cm (65) | 136 cm (55) | 126.5 cm (50) | 107.5 cm (43)

43 Starts From ₹ 25,990* Less Cashback* (T&C*)

NEW SERIES FOR 2025

P6K — TCL *PREMIUM* 4K HDR TV

Crystal Clear, Brilliantly Smart

185 cm (75) | 160.8 cm (65) | 136 cm (55) | 107.5 cm (43)

43 Starts From ₹ 21,990* Less Cashback* (T&C*)

S4K — TCL QLED TV

Restore true colours, see the world unfiltered

81.2 cm (32)

32 Starts From ₹ 11,990* Less Cashback* (T&C*)

S5K — TCL QLED TV

Restore true colours, see the world unfiltered

81.2 cm (32) | 107.5 cm (43)

43 Starts From ₹ 18,990* Less Cashback* (T&C*)

T&C Apply*

Available at

All Leading Consumer Electroinc Shops in Uttar Pradesh

UP West - Sunil Sharma : 9910349974
Lucknow Branch - Juned : 7897554445
Varanasi Branch - Ramkumar : 9838109000

All Leading Consumer Electroinc Shops in Haryana

Suresh Chandra : 7011099802

All Leading Consumer Electroinc Shops in Delhi & NCR

Sanjay David : 9871270725

All Leading Consumer Electroinc Shops in Punjab

Sanjay Kurana : 9780041403

NABCB
QMS 008
AN ISO 9001 -2000 COMPANY

IS:8931

CM/L-3228449

supreme
luxury bathing

Assuring Excellence in Bath Faucets

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

सुनहरी शुरुआत
बालवाटिका के साथ

शिक्षा की सशक्त बुनियाद हेतु

को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र वाले
विद्यालयों में

बालवाटिकाएं आरंभ

उपलब्ध सुविधाएं

- शैक्षिक सामग्री
- बाल मैत्रिक फर्नीचर
- आउटडोर प्ले मटेरियल
- गतिविधि आधारित किट : वंडरबॉक्स
- ई.सी.सी.ई. एजुकेटर
- स्टेशनरी एवं लर्निंग कॉर्नर
- सामुदायिक सहभागिता
- क्षमता संवर्द्धन हेतु सहयोग

शिक्षा और कौशल का संगम
'लर्निंग बाय डूइंग' कार्यक्रम

- सत्र-2024-25 से 2,274 उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में पाठ्यक्रम से संरेखित कौशल संबंधी गतिविधियों पर आधारित 'लर्निंग बाय डूइंग' शिक्षण आरंभ
- सत्र-2025-26 से 3,288 नए उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में आरंभ किए जाने का कार्य गतिमान

काम दमदार-डबल इंजन सरकार

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश